साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार

वर्ष 5 अंक 7 | प्रति सोमवार इंदौर, 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2011 | पृष्ठ 8 | मूल्य 2/- रुपए

कांग्रेस का हथियार है, आतंकवाद से कमाई

आतंकी घटनाओं से मिडिया और जनता का ध्यान लगाना

जांच जब शुरू होगी जब सबूत साफ हो जाये, घाव भर जायें, जनता भूल जायें तो फिर हिन्दू संगठनों पर आरोप लगा सके

मुंबई राष्ट्र की व्यावसायिक राजधानी में तीन धमाकों के बाद जिस तरह से गृहमंत्री चिदंबरम ने बयान दिया कि भारत दुनिया के सबसे अशांत पड़ोस में रह रहा है इसलिये भारत के हर शहर पर हमलों का खतरा हैं।

दूसरा भारत के भावी प्रधानमंत्री बनाये जाने वाले आतंक बढ़ाओ, दहशत फैलाओ, भ्रष्टाचार दबाओं की नीति पर चलने वाली कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने अपने आस्तित्व को सिद्ध करने बयान दिया कि आतंकी हमले किसी भी देश पर हो सकते हैं और हर आतंकी हमले को रोक पाना संभव नहीं अर्थात पूरे देश की जनता अगर हमारे भ्रष्टाचारों को कोसेगी तो ऐसे ही आतंकी हमले हम पूरे देश में करवायेंगे और जनता ऐसे आतंकी हमलों में मरने के लिये तैयार रहे, क्योंकि हमारा तो काम ही महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट, वसूली है, हमें चुपचाप झेलो नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो।

तीसरे कांग्रेसी श्वान दिग्गी दानव मौके और कहा हमारी स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है, वहां तो हर दिन और सप्ताह में धमाके होते हैं। अर्थात अगर हमारे महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट-खसोट, कुकर्मों का ज्यादा हल्ला मचाओगे तो पाकिस्तान की तरह हर दिन, हर सप्ताह यहां भी धमाके होंगे।

चौथे क्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने अपने केंद्रीय मंत्री पद गंवाने की भड़ास निकालते हुए अपने निकम्मेपन और नाकामी छुपाने के लिये बयान दिया सिस्टम में है खोट, आतंक से जंग में सीवीसी (सेन्ट्रल विजिलेंस कमीशन) और केग (कंट्रोलर आडिटर जनरल) रोड़ा बलपूर्वक इसके आगे और बढ़े तो रही-सही कसर कांग्रेस के नेताओं के बयान सुनकर जांच एजेंसियों ने पूरी कर दी कि अगर मुंबई के क्रमिक विस्फोटों में मात्र 18 लोगों की मौत और 131 घायल हुए यह गिनती बहुत ज्यादा बढ़ जाती अगर आतंकियों ने बम को सही तरीके से रखा होता, जांच अधिकारियों का मानना है कि आतंकवादियों ने जो भी बम बनाये वह बहुत ज्यादा मारक क्षमता के थे लेकिन इनको गलत ढंग से रखा गया, मसलन दादर में बस स्टॉप के ऊपर जंक्शन पर बम रखा गया, जिसकी वजह से बम का असर नीचे कम हुआ। झवेरी बाजार में छाते में बम रखा था, चूंकि छाता उलटा था इसलिये बम का असर ऊपर की तरफ ज्यादा हुआ। **(शेष पेज 2 पर)**

राष्ट्रगीत में 'अधिनायक' गुलामी का प्रतीक

राष्ट्रगीत में लोकनायक गायें, हटायें अधिनायक

जन,गण,मन, लोकनायक जय हैं, लोकनायकों को ही जनता चुनती है

हमारे राष्ट्र में राष्ट्र गीत के रुप में वर्तमान में गाया जाने वाला जन,गण,मन अधिनायक जय है। यह अधिनायक शब्द स्व. रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जार्ज पंचम की आगवानी में 1917 में लिखा था, जब राष्ट्र अंग्रेजों के अधीन था, फिर बंगाल में अंग्रेजों ने पहले कदम रखा था, और उसे अपनी तरह से अंग्रेजी तरीके से सजाया संवारा था, कलकत्ता ईस्ट इंडिया कं. का भारत की धरती पर पहला मुख्यालय था, कोलकत्ता में वर्तमान में उनकी बनाई अनेकों इमारतें और भवन उनकी सोच व अंग्रेजी संस्कृति का बखान करते हैं। इसलिये अधिकांश बांग्ला लेखकों में अधिकांश अंग्रेजी भाषा के ख्यात लेखक हुए हैं। जिनमें एक रविन्द्रनाथ ठाकुर भी थे, उस काल में इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस गीत को गुलामों की ओर से आंग्ल भाषा और संस्कृति प्रेमी बंगाली कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आगवानी में लिखा था, जिस आंग्ल ए ओह्यूम ने कांग्रेस पार्टी का गठन किया था, उसी कांग्रेस पार्टी को ही अंग्रेजों ने राष्ट्र की कमान सौंपी थी, स्व. पं. जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के कांग्रेस पार्टी द्वारा पहले प्रधानमंत्री बनाये गये, पं. नेहरु शुरू से ही राजनीति में व्यस्त रहने के कारण अपनी बिटिया स्व. इंदिरा गांधी की शिक्षा-दीक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, इस कारण उन्होंने स्व. ठाकुर के शांति निकेतन में पढ़ने भेजा था, बाद में स्व. ठाकुर ने उनके निकेतन का माहौल बिगाड़ने की शिकायत नेहरू से की, इस बात का जिक्र ज्यादा न फैले और उनकी नेताई छवि पर बेटी की उच्छृंखलता का दाग न लग जाये, इसलिये पं. नेहरू ने इसे ही राष्ट्रगीत बनाकर स्व. ठाकुर को अंधों की रेवड़ी की तरह राष्ट्रकवि का सम्मान देकर सदा के लिये उनका मुंह बंद कर दिया, बेशक पंडित नेहरू और महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद जानते थे कि यह गुलामी का गीत है, इसलिये उन्होंने वंदे मातरम् के इस गीत को गाकर ही जिसके दम पर हमने आजादी पाई थी, को भी राष्ट्रगान घोषित किया गया था, जब वंदे मातरम् आजादी के दीवानों में मातृभूमि को आजाद करवाने का जोश पैदा करता था, वो आजादी के बाद अब ये गीत देशभक्ति और साथ में रहने की प्रेरणा देता हैं।

बेशक समय माया ने जन,गण, मन अधिनायक जय है के इस गीत गाने के विरुद्ध अपने शैशव काल से ही आवाज उठाई, समय माया डॉट काम की साइट पर पिछले तीन वर्षों से समाचार पत्र में जन. 98 से लगातार प्रकाशन किया, इसके साथ सच यह भी है कि साइटों और समाचार पत्र के प्रकाशन पर भी केन्द्र व राज्य सरकार ने बराबर ध्यान दिया। **(शेष पेज 6 पर)**

पाक और चीन की नजदीकियां बढ़ा रही अमेरिकी परेशानियां

अमेरिका व नाटो नहीं छोड़ेंगे अफगानिस्तान

भारत के सामरिक हित में आर्थिक अहित

दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति अत्याधिक महत्वपूर्ण होने से ही ऐतिहासिक रूप से हजारों वर्षों से अफगानिस्तान पर हजारों आक्रमण हुये और वर्तमान में भी इसी भौगोलिक महत्व के कारण अभी भी वहां की भूमि रक्त रंजित रहती हैं, वह रक्त चाहे वहां मूल निवासियों का हो या आक्रांताओं का, पिछले 4-5 दशकों से वह रूस बाद में अमेरिकी प्रायोजित तालिबानों पिछले 10 वर्षोंय से सीधे अमेरिका और नाटो जैसे आक्रमणकारियों के युद्ध के जुनून, हथियारों के परीक्षण, प्रदर्शन और बिक्री का माध्यम होने के साथ ही दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण देशों से चारों तरफ से घिरे होने के कारण अमेरिकी दादागिरी के प्रदर्शन का प्रत्यक्ष अड्डा बना हुई है। अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हुए हमले के कारण को लादेन को जिम्मेदार बताते हुये जो हमला कर वहां जो अपनी प्रत्यक्ष उपस्थिति दर्ज कराई उसके मूल कारण

में था, अपने प्रायोजित आतंकवाद को प्रत्यक्ष सीधे सहायता देकर भारत, रूस, चीन, ईरान में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अस्थिरता फैलाना, उनके आर्थिक विकास को क्षति पहुंचा कर सामरिक रूप से मजबूत न होने देना ताकि फिर कोई रूस जैसा उसकी टक्कर में खड़ा होकर उसकी विश्व पर दादागिरी, गुंडागर्दी में हस्तक्षेप न कर सके, जबकि लादेन और तालीबान को अमेरिका ने ही अफगानिस्तान से रूसी फौजों और जासूसों को खदेड़ने के लिये ही विकसित किया था बाद में उसे टक्कर देने वाले उस सोवियत रूसी गणराज्य को 26 गणराज्यों में विभक्त कर ही चैन लिया, उसने 1970 से 1990 के बीच भारत, ईरान, पाकिस्तान और रूसी राज्यों में अपने इस ओबामा और तालीबान रूपी हथियार का प्रयोग कर न केवल इन राष्ट्रों में अस्थिरता फैलाई वरन अपने हथियार गोला बारूद, मिसाइलें, लड़ाकू जहाज भी खूब बेंचे। **(शेष पेज 3 पर)**

जो हश्र सूचना अधिकार का हुआ वही लोकपाल का होगा

चमत्कार नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ेगा लोकपाल कानून से...

सारे भ्रष्ट अश्वस्त एक श्वान को और रोटी खिलाएंगे भ्रष्टाचार की

पूरे विश्व में भष्टाचार के खिलाफ एक अरब लोगों की आवाज बन गए अन्ना हजारे का अनशन और उसमें जुड़ी युवाओं की भीड़ से बुद्धीजीवी खुश हैं पर यथार्थ में इस आंदोलन के ठोस राहत मिलने वाली नहीं है। यह वह अच्छी तरह जानता है। इसलिए बुद्धीजीवियों ने खुल कर समर्थन नहीं दिया।

क्यों कि वह अच्छी तरह जानता है कि एक नया कानून एक नई वसूली का हथियार, बिल्कुल वैसे ही जैसे यातायात पुलिस का कार्य यातायात सुधारना और मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करना पर यातायात पुलिस पुलिसिये नवसिखाड़ू रंगरूट को चौराहे पर खड़ा करके बाकी अधिकांश वसूली में जुटे रहते हैं। तेल लेने गया यातायात जाम होते चौराहे तिराहे व सड़कों पर गुथ्थम् गुथ्था होते वाहन हर छोर पर लंम्बी होती लाईन से ज्यादा जरूरी काम

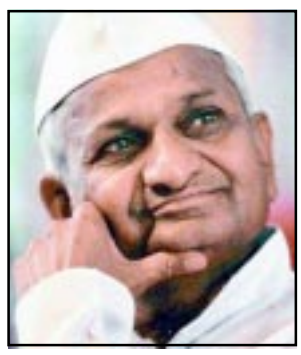

पुलिस वाले इधर उधर दो पुलिस वाले घेरने में और दो पूछताछ करने में और कागजात देखने और दिखाने में और अंत में ढेर सारी खामिया बताकर 1000 रुपये की रसीद कटेगी नहीं तो 500 रुपये दो दे दिये तो ठीक है नहीं तो थाने चलो। फिर 90 प्रतिशत स्वामी झंझट में उलझने से बेहतर कार वाले 500 और स्कूटर व मोटरसायकल वाले 50/100 रुपये की भेंट चढ़ाकर समय बचाना पसंद करते हैं।

ये जानबूझ कर भागते हैं। हर नया कानून पुलिसियों वकीलों की पोस्ट बारह करता है। या फिर संबंधित सस्थाओं कानून के आधार पर निर्मित और कार्य को संपन्न करने के लिए बनाई जाती है। जैसे कि सूचना के अधिकार के अधिनियम लागू होने के समय पूरे देश में राष्ट्रपति कार्या. से लेकर सर्वोच्छ न्यायालय उच्च न्यायालय से लेकर नीचे तक हर विभाग में दहशत थी लेकिन इस अधिनियम को लागू हुए 6 वर्ष हो गये हैं। क्या हुआ जब कि सूचना का अधिकार अधिनियम से बेहतर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए न तो इससे पूर्व कोई अधिनियम मजबूत था न इस अधिनिय के लागू होने के बाद ही कोई अधिनियम सूचना के अधि. का स्थान लो पाएगा।

(शेष पेज 5 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

लोकपाल, कानून, चिंतन और औचित्य

अन्ना आंदोलन के सामने सिर झुकाकर, धूर्त, मक्कार, भ्रष्ट, जालसाज सत्ताधीशों ने लोकपाल कानून बनाने, शर्तों के अनुसार उसमें प्रधानमंत्री को शामिल करने का वादा कर दिया, अन्ना उनके आंदोलनकारी और जनता सोच रही होगी कि आखिर जीत उनकी हो ही गई, सरकार ने जानबूझकर 16 अगस्त से अन्ना के आंदोलन और अनशन को जानबूझकर हवा दी गई, ताकि मीडिया और जनता का ध्यान उसमें उलझा रहे, जनता इस नाटक को देखने में व्यस्त थी और उसने राष्ट्र के सारे खाद्य व्यवसाय को रिलायंस को गिरवी करने हेतु खाद्य सुरक्षा और मानक अधि. 06 जो 2006 में ही पास हो गया था, जिसे सरकार जनता के विरोध के डर से लागू नहीं कर पा रही थी, अन्ना ने मई में 16 अगस्त से आंदोलन की घोषणा की थी, उसने अच्छा मौका देखकर मई में ही 5 अगस्त 11 से लागू करने की घोषणा कर 5 अगस्त 11 से लागू कर दिया, अर्थात लोकपाल बना नहीं बना, परन्तु अन्ना के आंदोलन ने सत्ताधीश धूर्तों को खाद्य सुरक्षा व मानक अधि. 06 के माध्यम से रिलायंस प्रेश के मालिकों को पूरे राष्ट्र के खाद्य व्यवसाय का थोकपाल बनाकर हर वर्ष 10-20 हजार करोड़ रु. के कमीशन को डकारने की व्यवस्था अवश्य कर ली, 'कानून धूर्तों के बनाये शब्दों के मायाजाल हैं, जो अपने हित साधन में जनहितों के शोषण के हथियार होते हैं।' भारत में आजादी के बाद से बनाये गये अधिकांश कानूनों के सूक्ष्म अध्ययन से यह निष्कर्ष सत्यार्थ सिद्ध हो जायेगा। अब यदि चिंतन करें यदि एक लोकपाल कानून बन जाने से यथार्थ में क्या होगा? यथार्थ में भ्रष्ट सचमुच पकड़े जायेंगे? राष्ट्र में दहशत से भ्रष्टाचार करना छोड़ देंगे, फिर क्या लोकपाल बनाये जाने वाला व्यक्ति इस धरती का निवासी ना होकर, आसमान से उतरा कोई देव पुरुष होगा, जिसे लाभ, भूख, काम, मद, मोह, माया नहीं छूयेगी, स्वाभाविक है वह भी मानव होगा और मानवीय दोषों से युक्त होगा, लोकपाल का पद पाते ही और लोकपाल विभाग में आते ही वह भी दोनों हाथ वसूली कर पुलिस, लोकायुक्त व जांच एजेंसियों की तरह अपनी सार्थकता सिद्ध करेगा। इतिहास गवाह है कि सारी एजेंसियां उल्टे ही भ्रष्टों का हथियार बन गई, जैसे कि सीबीआई, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इंवेस्टीगेशन बनकर उल्टे ही कांग्रेस का अल्पसंख्यकों के नाम पर मुस्लिमों को खुश करने, हिन्दू नेताओं, संतों को परेशान करने का हथियार बन हिन्दुओं को कांग्रेस के डमरू की तरह नाचने के लिये धमकाता है।

अन्ना और उनके अनुयायियों को ये चिंतन करना चाहिये कि आखिर ऐसे कानूनों का औचित्य आने वाले समय में एक नई वसूली एजेंसी में बदलकर भ्रष्टों को बचायेगा और ईमानदारों को परेशान करने का हथियार न बन जाये, क्योंकि वर्तमान कानून में भी सब बराबर है। चाहे वह प्रधानमंत्री हो या पटवारी, आवश्यकता तो इस बात की है कि कानूनों का पालन करवाने वाले ही ईमानदार नहीं है।

सूचना का अधिकार अधि. 05 को लागू हुए 6 वर्ष बीत गये किस सरकारी विभाग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कार्यालय से लेकर सभी केन्द्रीय और 30 राज्यों के 125 से ज्यादा विभागों ने धारा 4 के अंतर्गत जानकारी को इंटरनेट साइटों पर लोड करने के अतिरिक्त अपने कार्यालयों में अवलोकन के लिये जनता को प्रस्तुत करवाई, जबकि अरबों रु. के केवल बिल लगा दिये जाते हैं।

दुधारु जानवरों के पैरों में फैल रहा खुरपका

पूरा बकवास है, पशु चिकित्सा व पशु संवर्धन

रु. 800 करोड़ चर जाते हैं, मंत्री से लेकर चिकित्सा इकाईयों के डाक्टर

म.प्र. के मुख्यमंत्री शि.रा.सि. चौहान बातें बड़ी मीठी और मासूमियत से करते हैं। समय माया पिछले एक महीने से पशु चिकित्सा विभाग के भ्रष्टाचार और गाय भैंसों के पैरों में हो रहे खुरपका रोग और उनके सड़ते पैरों के बारे में लिखकर पूरी दुनिया को जानवरों की पीड़ा पर लिख रहा है। परिणामों में केवल मुख्यमंत्री और उनका वह महा भ्रष्ट पशु स्वास्थ्य मंत्री अजय विश्नोई केवल लंबी-चौड़ी घोषणायें कर रहे हैं।

मीडिया में भी हल्ला मच रहा हैं। पर वास्तविक परिणाम उन मूल पशुओं की पीड़ा के शमन के रूप में सामने नहीं आ रहा और दर्द से कराहती गायें समय माया के कार्यालय के सामने सुबह से ही आकर पीड़ित पैरों को पटक-पटक कर पीड़ा शमन की गुहार लगा रही हैं।

इस संबंध में श्री अजमेरा ने इंदौर के महूनाका स्थित कार्यालय में जाकर उपसंचालक पशु चिकित्सा से भी निवेदन किया और बजट के बारे में जानकारी मांगी, वो महाजानवरों की फौज जो दलीलें देती है। न केवल पूर्णतः औचित्यहीन होने के साथ ही सूचना के अधिकार में भी जानकारी नहीं दी जा रही है। दो महीने से ज्यादा समय जबकि इसकी प्रथम अपील भी कर दी गई है। परन्तु इंदौर संभाग के आठों जिलों और उज्जैन संभाग के 6 जिलों की जानकारी 3 माह बाद भी अप्राप्त है।

इस संबंध में पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा मंत्री अजय विश्नोई से भी कहा गया परन्तु वह भी वही दलील देने लगे कि हमारे विभाग के डॉक्टर्स जानवर ढूंढकर इलाज करने तो नहीं जायेंगे। जब उनसे पूछा गया कि जब आपके शहरीय तहसीलों, विकास खण्डों और ग्रामीण पशु चिकित्सा विभाग की अधिकांश इकाईयां ही बंद रहती हैं। अधिकांश डॉक्टर्स, शहरी मुख्यालयों के आस-पास ही मंडराया करते हैं। तो पशु पालक कहां और किसके पास जायें। ग्रामीण पशु चिकित्सालयों का तो ये हाल है कि वहां महीनों से ताले ही नहीं खुलते हैं। दरवाजों पर जालें और ताले जंग खा जाते हैं। तो वही रटा-रटाया जवाब मिला कि आप लिखकर भेजिये मैं कार्यवाही करूंगा।

पाठकों को बता दें कि ये वही भ्रष्ट मंत्री है जिसे पहले मानव स्वास्थ्य सेवाओं और परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया था, भारी भ्रष्टाचार के चलते इन्हें वहां से इनके भ्रष्टाचार दवा खरीदी घोटाले, सामग्री खरीदी घोटाले के चलते खदेड़ा गया था, पुर्नवास के तहत इन्हें पशु चिकित्सा विभाग में बैठाया है, अब बेचारे मूक जानवर इन विभागीय डॉक्टरों से लेकर मंत्री, संत्री और मुख्यमंत्री की शिकायत किससे, कैसे करें, कि ये हरामखोर धूर्तों की फौज केवल कागजी खानापूर्ति कर सारा पैसा हजमकर जाती है।

एक पशु चिकित्सा जिला मुख्यालय पर 32 हैडस में पैसा आता है। हाल ही में प्राप्त रतलाम जिले की प्राप्त जानकारी जिसमें 32 हैडस में रु. 3 करोड़ 20 लाख 3 हजार 900 रु. प्राप्त हुये थे। 10-11 में, अधिकारियों - कर्मचारियों के वेतन भत्ते इसमें शामिल नहीं है। वह भी लगभग इतना ही होगा अर्थात रु. 6 करोड़ खर्च करने के बाद भी इस विभाग के दो पायों के पास ये जवाब भी नहीं होगा, कि इन्होंने वास्तविकता 6000 पशुओं की भी वर्षभर में चिकित्सा की होगी, या 6000 पशुओं की बढ़ोतरी इनके प्रयासों से की गई होगी, यह हाल पूरे प्रदेश का ही है। कहीं कुछ 5 से 10 हेडस बढ़े होंगे कहीं कम हुये होंगे। इस प्रकार पूरे प्रदेश भर में हर वर्ष रु. 700 से 800 करोड़ का बजट हजम कर लिया जाता है।

भाजपा वैसे तो गायों, बैलों और बछड़ों को हिन्दू धर्म की आस्था के अनुकूल बड़ा पूज्यनीय मानती है। साथ ही उसके पूरे प्रदेश में हजारों गौसेवा केन्द्र भी उसके कार्यकर्ताओं और अनुयायियों द्वारा चलाये जा रहे हैं। बजरंग दल, शिवसेना, विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में हजारों जानवरों को गाड़ियों से उतारकर जो कत्लखानों में ले जाये रहे होते हैं, बचाते हैं। पर ये जानवर जो खुरपका की पीड़ा से तड़पकर प्राण त्याग रहे हैं, किसी भी कार्यकर्ता को भी नहीं दिख रहे।

गौशालाओं के धूर्तों को भी सरकार से मिलने वाला अनुदान भर चाहिये। वास्तविकता में तो अपनी रोजी-रोटी चलाने का बहाना ही भर है गौशाला चलाना। भाजपा और उसके अनुषांगिक संगठन भी गौमाता के नाम पर नौटंकी तो बहुत करते हैं पर वास्तविकता जमीन सच्चाइयों से बहुत दूर हैं। वर्तमान में यही कारण है कि प्रदेश की 7 करोड़ 25 लाख की आबादी को दूध की आवश्यकता को पूरा करने के लिये प्रदेशभर में 1 करोड़ पशु भी नहीं है। प्रदेश की कुल आबादी को आधा ली औसत के मान 4 करोड़ ली. दूध की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। जबकि उत्पादन मात्र 50 लाख पशुओं से मात्र डेढ़ करोड़ ली. दूध उत्पादित होता है। परिणामस्वरूप लगभग ढाई करोड़ ली. दूध नकली बनाकर प्रतिदिन पूरे देश में खपाया जा रहा है।

आतंकी घटनाओं से मिडिया और जनता का ध्यान बांटाना

पेज 1 का शेष

ओपेरा हाउस में बस गड्ढे में 60 के बजाय 30 डिग्री पर रखा था। इसलिये इस बम का असर भी उतना नहीं हुआ, जितनी मारक क्षमता का यह बम था, अर्थात जांच एजेंसियों से पूछ कर और उनकी सलाह पर लगाये गये होते तो बेहतर परिणाम सामने आते।

कम से कम 100 मरते और 500 घायल होते, कांग्रेसियों की प्रत्यक्ष हिम्मत नहीं पड़ी वरना तो जांच एजेंसियों से मिलकर ही अंजाम देती ताकि बेहतर तरीके से दहशत फैलाकर दोनों ही दोनों हाथ वसूली करते, अर्थात एक तरफ आतंक की आड़ में मुंबई में फैला दाउद का नेटवर्क मोटी वसूली करता और दूसरी तरफ मुंबई पुलिस और सभी जांच एजेंसियों को भी मोटी वसूली बांटता है। इसलिये पूरी मुंबई पुलिस उसके इशारों पर नाचती है। यही हाल प्रशासन और कांग्रेसी गठबंधन शासन जिसमें नेशनल कांग्रेस पार्टी भी शामिल हैं।

आखिर ये माफियाओं के रु. 10000 करोड़ प्रतिमाह के कारोबार में भी तो हिस्सेदार हैं। जिसमें रु. 1000 करोड़ प्रतिमाह से ज्यादा की वसूली केवल गुंडागर्दी और दहशत के बल पर की जाती हैं। जिसमें हताश उद्योगपति, लाखों दुकानदार, बिल्डर, ठेकेदारों के साथ नर्सिंग होम्स स्कूल्स, कालेजेंस, कंपनियां फर्में सभी शामिल हैं। रु. 1000 करोड़ की कमाई तो सट्टे वालों से ही हो जाती है। वहां पर चले 150 से ज्यादा थानों के थानेदारों की कमाई ही रु. 5 से 10 करोड़ प्रतिमाह होती है। आखिर कहां से और किस लिये आता है। स्वाभाविक है सारा पैसा अपराधियों से ही मिलता है। ऐसे धमाकों से तो न केवल पुलिस वरन गुंडों की कमाई में भी हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाती है। स्वाभाविक है उसमें भी इन्हीं पुलिस अधिकारियों की कमाई भी बढ़ जाती है। इसलिये ही हमारे गृहमंत्री चिदंबरम ने धमाकों के बाद बयान दिया कि 30 महीने तक तो बचाया मुंबई को, आखिर नुकसान झेलने की भी कोई हद होती है।

आखिर सत्ताधीश होने का मतलब क्या है? यदि हम सत्ता में हैं, तो जनता को हमारे सामने सिर उठाकर जीने का हक नहीं है। सामने से महंगाई, करों के बोझ से जनता को लूटो, दूसरी ओर पीछे से आतंकवाद, दहशत, गुंडागर्दी और भाईबाजी से गुंडे, मव्वाली, माफियाओं, दादा-पहलवानों जो हर छोटे-बड़े शहरों से लेकर महानगरों तक हर चप्पे-चप्पे में अपना वसूली के नेटवर्क न केवल बाहर रहकर वरन जेलों तक से और विदेशों में रहकर भी देश में चलाते हैं। पुलिस प्रशासन, नेता, मंत्री तक ऐसे गुंडे माफियाओं की जी-हजूरी में बिछे रहते हैं। इसके सीधे से नमूनों के रूप में दाऊद और उसके भारत में फैले वसूली गिरोह को देखिये, उसके रिश्तेदारों और गिरोह के लोगों को, महाराष्ट्र पुलिस कैसे आंखों पर बिठाये रखती हैं, वहीं हाल छोटा राजन और उसके रिश्तेदारों और गिरोह का भी है। इन दोनों का भारत से पलायन किये वर्षों गुजर चुके हैं। इसके विपरीत भारत का मुंबई स्थित बालीवुड में फिल्म में पैसा लगाने से लेकर न केवल नायक-नायिकाओं के चयन से लेकर एक्स्ट्रा तक के सारे कारोबार पर दाउद का ही नियंत्रण हैं। उसकी जेट एयरवेज है।

लोटस जैसे पूरे भारत में बड़े-बड़े स्टोर्स हैं। न केवल पुलिस, प्रशासन, सीबीआई, एनआईए, एनएसजी, रॉ से लेकर पूरा गृह मंत्रालय के बीच और महाराष्ट्र का सब जानता है आकिर ये पैसा जो हजारों करोड़ में कहां से आया पूरा अवैध वसूली का ही है। जेट में दाउद के पैसे की बात उठीं, मिडिया में मामला उछलता रहा और ठंडा होता रहा।

पर हरामखोर जालसाज गृह मंत्रियों चाहे वह कांग्रेस का हो या भाजपा का किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगी, आखिर जूं रेंगती भी कैसे सभी तो पुलिस प्रशासन, राज्य सरकारों से लेकर केन्द्र तक बंदरबांट में शामिल रहते हैं। चारों तरफ मुखेरे श्वानों की फौज बैठी है। फिर मंत्री तो 5 वर्ष का मेहमान है। जबकि पुलिस प्रशासन में राज्य से लेकर केन्द्र तक अधिकारियों की डकैत फौज 35 से 40 वर्ष तक के लिये सरकारी दामाद जो जनता की जेब से वसूले गये करों से वेतन लेकर जनता के सीने पर ही बमों के विस्फोट करवाकर अपनी कमाई की रोटी सेंकती है।

यही कारण है कि महाराष्ट्र पुलिस से लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय सुरक्षा सैनिक, अनुसंधान और विश्लेषण विंग के बीच गृह मंत्रालय तक मुंबई के इन तीनों धमाकों के बारे में महीने भर बाद भी कोई ठोस तथ्य नहीं जुटा पाया। अभी तो यही निश्चित नहीं कर पा रही है, महाराष्ट्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय की जांच कौन करेगा।

आपस में ही जूतम पैजार हो रही है। यह जूतम पैजार का मौका स्वयं महाराष्ट्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय दे रहा है। ताकि सारे सबूत मिटवायें, मरने वालों के रिश्तेदारों की आंखों के आंसू सूख जाये, घायल और बच जाने वालों के घाव भर जायें और सब भूल जायें ताकि ये फिर से जैसा कि इन राज्य के और केंद्र के हरामखोर, जालसाज, गिद्ध मंत्रियों ने तत्काल बाद वक्तव्य दिये, हिन्दू संगठनों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना आदि के सक्रिय कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा सके और सुनील पुरोहित, प्रज्ञा, असीमानंद की तरह उन्हें अंदर कर हिन्दुओं का डरा-धमकाकर दहशत फैलाकर, मुस्लिमों को अपना हितैषी बनाकर वोट कबाड़ सके।

देवास-राऊ बाईपास अनुबंध को सौंपे सीबीआई को

पेज 8 का शेष

न ही ये धूर्त शूकर सूचना के अधिकार में जानकारी देता हैं, भोपाल में बैठे मुख्य परियोजना अधिकारी को अपील भी लगाओ तो सारे हरामखोर जालसाजों की फौज गांगरौनी तोते की तरह रटी-रटायी भाषा बोलकर अपनी खाल बचाने के साथ पूरे प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों जो लगभग 4700 कि.मी. के ठेकेदारों को बचाने में लगे रहते हैं। जबकि प्रदेश के पूरे राजमार्गों की हालत भारी खतरनाक और जानलेवा स्थिति में हैं, जो परियोजनायें पूरी हो गई हैं। उन पर जालसाज ठेकेदार वसूली तो पूरी कर रहा है, जैसा रा.रा. क्र. 3 इंदौर सेंधवा पर बाकी अधिकांश परियोजनाओं में वर्षों बाद भी न तो काम ही पूरा हो पा रहा है, न ही राज्य सरकार से मोटरेवल सड़कें लेने के बाद उन सड़कों पर वाहन चलने योग्य रखरखाव किया जा रहा है।

बेशक देवास-राऊ बाईपास के जालसाज ठेकेदार को बिना काम किये टोल वसूली के षड्यंत्रों में जनता की हाय और बद्दुआयें ही ले डूबीं, जब वाईएसआर रेड्डी ने इस टोल पर वसूली के प्रयास किये यहां तो उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश तो लगा ही साथ ही हैदराबाद स्थित इस भ्रष्ट जालसाज के साम्राज्य की चूलें हिलने लगीं और सीबीआई के भी छापों में षड्यंत्रों से कमाई दौलत भी सामने आ गई। एफआईआर में भी नाम शामिल कर लिया गया। ऐसे गर्म तवे पर यदि म.प्र. सरकार सर्वोच्च न्यायालय में तरीके से दावा दायर कर दे, तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। पूरे म.प्र. के रा. राजमार्ग के ठेकों के अनुबंधों का अध्ययन कर न केवल ठेकेदारों वरन पूरे भा. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कानूनी तरीके से उपलब्ध कर सड़कें पुनः प्राप्त कर छीनी जा सकती हैं अन्यथा 2013 के चुनाव में ये सड़कें दुःसाहसी सिद्ध होंगी।

विद्युत मंडल भी चढ़ गये सत्ताधीशों की लालच की भेंट

लूट और भ्रष्टाचार के लिये बढ़ाई जाती है बिजली की कीमत

वसूली, वितरण सुधार व अन्य सब सत्ताधीशों के ठेकेदारों को

भारत के विश्व व्यापार संगठन की तर्ज पर नाचने और उनकी इच्छानुसार हर कार्य और सेवा के बदले लाभ का मूल्यांकन और हर व्यापार को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनुकूल बाजार का स्पर्धात्मक मूल्यांकन हो, इसलिये शासकीय अरबों रु. की संपदा पर सत्ताधीश गिद्ध अपना कब्जा कर सकें या उनके रिश्तेदार, नातेदार अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियां, राष्ट्र के दुष्ट गिद्ध पूंजीपति, उद्योगपति यथा भारत के टाटा, बिरला, अंबानी, भारती व अन्य सैकड़ों जालसाजों की कमान सौंप कर उनसे औने-पौने सौदों को अंजाम देकर मोटा कमीशन डकारा जा सके, जैसा कि राष्ट्र के विद्युत मंडलों की संपत्तियों को सौंप कर सा कि सड़कों के बीओटी ठेकों के मामलों में हुआ। चाहे तो रोड डकैत कार्पोरेशन के हो, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के ठेकों से लेकर नगर निगमों, सैकड़ों सरकारी कार्यालयों, संस्थानों में हो रहा है और म.प्र. सड़क परिवहन निगम को बंद करके उसकी खड़ी परिसंपत्तियों के मामले में म.प्र. सरकार चाहे तो पुरानी कांग्रेस की हो या वर्तमान भाजपा की सरकार कर रही है। वही हाल ये हरा मक्कार धूर्त, गिद्ध मंत्रियों और इंडियन एब्यूसिंग सर्विस के अधिकारी मिलकर कर रहे हैं।

म.प्र. विद्युत मंडल एक लाभ में चलने वाला संस्थान था, पर जब से इसमें इन गिद्ध आई.ए.एस. की गिद्ध लॉबी को बैठाया गया इन हरामखोरों शूकरों की फौज ने उसे नोंच मारा, वि.व्या.सं. के इशारे पर केंद्रीय मंत्रियों ने मोटी रकम डकार कर राष्ट्र की मिश्रित अर्थव्यवस्था को नकारते हुए अपनी कमाई के लिये पूंजीवाद की ओर धकेलते हुए राष्ट्र के विद्युत मंडलों को खंड बिखेर कर कंपनियों में बांट दिया, फिर उन कंपनियों का प्रबंध संचालक और अध्यक्ष भी आई.ए.एस. बनाकर कर बैठा दिये गये, ये इंडियन एब्यूसिंग सर्विस अर्थात भारतीय गाली देने वाली सेवायें के इन अधिकारियों जो महा हरामखोर, महा निकम्मे उन गिद्धों की फौज है जो किसी भी विषय के विशेषज्ञ नहीं है। यहां तक कि न तो इन्हें प्रशासनिक कानून जानते हैं, न पूरी प्रशासनिक पद्धति, मुश्किल से 10-20 % पूरे देश के आई.ए.एस. अधिकारियों के विचारों में स्पष्ट और घनात्मक सोच व कार्यप्रणाली होती हैं, अंदाज लगाया जा सकता है कि ऐसे धूर्त, मक्कारों पूरी विद्युत तकनीकी को तो बहुत दूर अवसद भी नहीं आता, फिर ऐसे गधों को देश के विद्युत मंडलों की इंजिनियर लॉबी जानती है, इन मुखेरे श्वानों का कैसे मुंह के साइज का टुकड़ा डालकर मुंह बंद रखना है। फिर इन एमडी/सीएमडी की बला से क्या ऐसा किया, क्या सायकल, क्या हर्टज फ्रिक्वेंसी, बस पैसे वसूलने का सायकल चलता रहे, ताकि सीएमडी और उसको बैठाने वालों का ही खुश बना रहे, धन आने की फ्रिक्वेंसी नियमित बनी रहे, इससे ज्यादा इन्हें मतलब नहीं, कौन सा मुख्य अभियंता क्या खरीदी कर रहा है, क्या काम कर रहा है से लेकर सुपरवाइजर तक जो भी है पुराने घाघ इंजीनियर संभालते हैं। अंदाज इस बात से ही लगाया जा सकता है, एक महाधूर्त, महाभ्रष्ट, जालसाज उपयंत्री पूरे म.प्र. के म.प्र. विद्युत मंडल के अभियंता संघ का अध्यक्ष बना बैठा जा.के. वैष्णव पिछले 20 वर्षों से अपनी दुकानदारी जमा कर बैठा है।

अकेले इंदौर में ही 25 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का मालिक है। इसकी दुकादारी का अंदाजा बिलों के सुधारने, लाइट काटने जोड़ने में ही इस धूर्त ने पिछले 10 वर्षों से वेयर हाउस जोन पर बैठकर ही औसतन प्रतिदिन 50 हजार तक कमाये। यह कमाई केवल बिलों की घट-बढ़ काटने जोड़ने, तोड़ने मरोड़ने की थी, अभियंता संघ के सुपरवाइजर से लेकर कार्यपालन अधीक्षण और मुख्य अभियंता के स्थानांतरण पदस्थापना तक का पूरे म.प्र. का खेल यह धूर्त बंदा लाखों के सौदे में करता है। जिसकी औसतन कमाई सूत्रों के अनुसार न्यूनतम 10 से 25 लाख रुपये महीने तक होती है। 25-50 स्थानांतरण प्रकरण किसी न किसी बहाने इसके हाथ में रहते हैं। पिछले 10 वर्षों से यह वेयर हाउस जोन पर रहकर बिना

किसी लिखित स्वीकृति के इसने उस परिसर में अपना एक अलग कंम्यूटरीकृत, एसी कार्यालय बना रखा था, इस श्वान ने इंदौर में अपना स्थाई कमाई का अड्डा बनाये रखने के लिये अभियंता संघ के लेटर पेड से अधियंता और उपभोक्ताओं के विरुद्ध शासन के धूर्त गिद्धों मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (ऊर्जा), सचिव, मंडल, मुख्यमंत्री के साथ चंद टुकड़ों की खातिर आंख मींच कर अनुबंध हस्ताक्षरित किये, इन सबका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं, 1995-96 से हर वर्ष में दो बार किसी न किसी बहाने बिजली की कीमतें बढ़ाई जाती रही हैं और ये चुपचाप इंदौर में जमे रहने अपनी दुकानदारी से अध्यक्ष होने के लाभ लेकर, बिना चिट्ठे और लाभ-हानि के अध्ययन के ही हस्तांनतरित होते रहे, पिछले अनेकों लेखों में समय माया ने तकनीकी कमाई के पहलुओं से लेकर जिनमें सारणी के संजय गांधी ताप विद्युत ग्रहों से लेकर जिन्हें कभी कोयले के नाम पर, कभी रख-रखाव के नाम पर जानबूझकर ये धूर्त आईएएस अधिकारी विद्युत उत्पादन कं. का अध्यक्ष भी है, बंद करना चाहते हैं, ताकि अधिकांश विद्युत निजी कंपनियों यथा पय पावर रिलायंस, जिंदल व अन्य अनेकों कं. से महंगी विद्युत खरीदकर बीच में मोटा कमीशन गिद्ध मुख्यमंत्री, सचिव, प्र. सचिव सुलेमन से लेकर कं. के सीएमडी, मु. अभि. अधी. अभि. कार्य. अभि. से लेकर उपयंत्री तक जिसको जहां जैसा मौका मिल रहा है वसूली कर रहा है।

जहां तक मुख्यमंत्री शिवराज से लेकर उनके 20 कैबिनेट स्तर के मंत्री, 3 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्री और 9 राज्य मंत्री आये तो सभी नोंचने खसोटने और वसूली करने के लिये ही है। पर जितना टुकड़ा उनके सचिव, प्र. सचिव, उनको डालते हैं, उतना ही डकार पाते हैं। जहां तक ऊर्जा मंत्री राजेन्द्र शुक्ल का सवाल है, तो रीवाड़ी तो खुद ही पुराना खदान माफिया है। अरबों रु. रायल्टी चोरी पिछले 25-30 वर्षों में की, 4 विद्युत वितरण कं. और उत्पादन कं. में पहले से ही जो घाटे दिखाकर अरबों रु. की सीएमडी डकैती डालता है जो लगभग रु. 10 अरब प्रति कं. जिसमें खरीदी के नाम पर रखरखाव के नाम पर रु. 5-7 अरब की झूठी बिलिंग की जाती है। दूसरी ओर खरीदी गई बिजली के 40 से 200% अधिक की वसूली घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं से कर ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं से कर अरबों रु. के बिलों में हेराफेरी करवाने, सीधे 50% पर छोटे से लाइनमेन, मीटर रीडर से लेकर ऊपर बड़े-बड़े उद्योगपतियों, फैक्ट्री संचालकों आदि में हर शहर, औद्योगिक केन्द्रों में जैसे पीथमपुर, देवास, मालनपुर जैसे 50 से ज्यादा केन्द्रों पर रु. 2 अरब से ज्यादा की बिजली जानबूझकर चोरी करवाकर, सीधा पैसा डकारा जाता है। इंदौर के इलेक्ट्रानिक कॉम्पलेक्स जोन पर बैठा सहा. मंत्री चौधरी की कार्यप्रणाली देखने से और जानकारी एकत्र करने से ज्ञात हुआ कि ये निहायत लट्ठ, बतमीज, उपयंत्री से पदोन्नत डिप्लोमाधारी को यहां क्यों बैठाया गया है, जबकि टाटा, बिरला, भारती की टाटा टेलीकॉम, बिरला की आइडिया, भारती की एयरटेल जैसी बड़ी जालसाज कं. की औद्योगिक इकाइयां के साथ अनेकों अन्य 50 छोटी-मोटी इकाईयां से यहां पर कार्यरत इस गिद्ध चौधरी की बिलों में छूट देकर लूटने की खुली कार्य प्रणाली से स्वाभाविक है, रु. 25 लाख की कमाई पर कम से कम एक करोड़ रु. की बिजली चोरी करवाई जाती है। ये इतना हरामखोर है कि गरीबी रेखा में लगने वाले घरेलू कनेक्शन पर इस इसे रु. हजार चाहिये थे, इसलिये उस गरीब यशवंत भदौरिया को इसने और वहां बैठे मक्कार बाबुओं के स्टॉफ ने महीनेभर से ज्यादा नचाया। इसी जालसाज चौधरी ने एक दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कर्मचारी सुरेश को 5 खंभों पर चल रही एलटी लाइन के तारों को काटकर लाने का आदेश दे दिया। जिस पर किसी प्रकार के कोई कनेक्शन नहीं थे, इसको खंभे उखड़वाकर कहीं ओर लगवाकर वसूली करना थी और तार निकलवाकर हजम करने की नीयत उस बंदे सुरेश को बिना कार्यालय की जानकारी के भेजा। बेचारा तो खंभे पर चढ़ा और हाथ लगाते ही उसके दोनों हाथ जल जाने से गिर पड़ा। उसके दोनों हाथ कट गये, ये गिद्ध पलट गया कि मैंने उसे नहीं भेजा था, जांच बैठी, इसने टुकड़े डालकर जांच करने वाले श्वानों का मुंह बंद कर जांच इसके पक्ष में चली गई और वो बेचारा सुरेश अपाहिज बन जिंदगी जी रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पूर्व का म.प्र. विद्युत मंडल, ऐसे ही मंडल को अपनी लूट खसोट और वसूली के लिये कंपनियों में बांटा पहले केन्द्र सरकार के इशारे पर, जब नीचे दिग्गी दानव को कहानी समझ आई, तो उसने अपने भाई की फर्म से ही रु. 1500 करोड़ के इलेक्ट्रानिक मीटर खरीदवा कर एक तरफ जनता की जेब पर डकैती डाली दूसरी तरफ रु. 140 का मीटर रु. 950 से 1500 में खरीदी करवा कर रु. 800 करोड़ नोंच मारा से लेकर अभी तक बिल वसूली की फ्रेंचायजी, बिल बनाने, कॉल सेंटर चलाने, बिजली सुधार आदि सब अपने भाई भतीजों को बांटकर जनता से और कंपनी दोनों तरफ से वसूली की जा रही है। जिसकी लूट का बोझ घाटे दिखाकर बिजली की कीमतें बढ़ाकर जनता से वसूलकर डाके डाल रहा है। विद्युत मंडल से कंपनियां बनाई गई, कार्य शैली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिनों दिन उपभोक्ता बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर लगातार स्टॉफ घटाया जा रहा है, जैसे मंडल की जीपें, विद्युत संयोजन बिगड़ने पर एक फोन करने पर दौड़ पड़ती थी, अब फाल्ट रिपेयरिंग की पूरी टीम इंदौर में ही घटाकर 25 से 50 व्यक्तियों का कर दिया गया जो सीढ़ी लेकर सायकलों पर तीन-चार घंटे बाद तक पहुंच पाता है। ठेकेदारी पर मीटर रीडर काम करते हैं, जो हजारों अवैध कनेक्शनों लाखों रु. वसूलकर अपनी जेबों में रख लेते हैं। जिसमें ठेकेदारों और इंजीनियरों का भी हिस्सा होता है।

सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने के लिये इस विद्युत वितरण कं. को 18/6/11 को पत्र दिया, हरामखोरों ने आवेदन का जवाब पत्र क्र. 15222 से दि. 18.7.11 को ही दिया ताकि शूकरों की फौज मामले को अपीलों में उलझाकर जानकारी देने से बच सके, अपील लगाई गई, उसमें भी श्वानों ने जानकारी न देने के लिए दलीलें पेशकर दी, जो इन डकैतों की बदइंतजामियों और भ्रष्टाचार को सिद्ध करता है।

इसका हाल भी सत्ताधीश इंडियन एब्यूसिंग सर्विसेज के अधिकारी म.प्र. सड़क परिवहन निगम की तरह ही करने पर तुले हैं। ताकि ये गिद्ध उसकी संपत्तियों और आय की नोंच खसोट करते रह सकें।

अमेरिका व नाटो नहीं छोड़ेंगे अफगानिस्तान

पेज 1 का शेष

अमेरिका वर्तमान में भले ही विश्व का अपने आप का दादा और गुंडा समझ रहा हो पर उस संकर प्रजाति के मानवों के देश को सोवियत रूस के टुकड़े कर देने की भयानक भूल का अहसास भी अवश्य रहा होगा, जब तक सोवियत रूस था, तब तक न केवल अमेरिका वरन सभी नाटो सदस्य जिसमें ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जैसे देशों को भी अपने नये हथियार बनाने, बेचने और कमाई करने का भी खूब मौका मिलता था, यदि सोवियत रूस अपने तरीके से चल रहा होता उसके टुकड़े नहीं हुये होते, तो विश्व का अमेरिका और रूस में जो ध्रुवीकरण हो चुका था, तो अमेरिका किसी देश को सहयोग करता था तो रूस उसके शत्रु राष्ट्र को सहयोग करता था और युद्ध की स्थिति में दोनों राष्ट्र उन लड़ने वाले राष्ट्रों को अपने हथियार बेचकर अपनी अपनी अर्थव्यवस्थायें चलाते थे, 1979 में ईराक ने ईरान पर आक्रमण किया तो ईराक को अमेरिका से गोलाबारूद, हथियार, लड़ाकू जहाज, पनडुब्बियां, युद्धक जहाज मिलते रहे और ईरान का वही मदद रूस करता रहा और 8 वर्ष तक युद्ध चलने में लड़े भले ही वे दोनों देश परन्तु अमेरिका और रूस की अर्थव्यवस्थायें बड़ी शान से चलती रहीं, अब जब सोवियत रूस के 26 टुकड़े अमेरिका ने अफगानिस्तान में स्व. ओसामा बिन लादेन और उनके तालिबानों को साथ लेकर गोरवाचौब के माध्यम से बिखेर दिये हैं। स्वाभाविक था अब रूस महाशक्ति नहीं रहा, वर्तमान में उसकी अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं चल पा रही है। इसलिये तालिबानों की आड़ में वह इस दक्षिण एशिया के इस अड्डे पर जमा रहकर ही रूस, चीन, भारत को अपने आतंकवादियों और पाकिस्तान को साथ लेकर अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर करने और सामरिक व्यवस्थाओं का मजबूत न होने देने भारतः पाकिस्तान और चीन को लड़वाकर अपने हथियार बेचने के बाजार को बनाये रखेगा, बेशक नाटो समूह के कुछ राष्ट्रों को अपनी सेना को अफगानिस्तान में महंगा पड़ रहा है, जिसमें मुख्य रूप से ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और फ्रांस हैं। इसलिये ये बार-बार घोषणायें करते हैं कि हम अपनी सेनायें अफगानिस्तान से शीघ्र हटायेंगे, क्योंकि तत्काल में उन्हें उसका कोई लाभ नहीं दिख रहा, जिससे नाटों राष्ट्रों में अपने इस अनावश्यक आर्थिक बोझ को लेकर बौखलाहट है।

अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजों का जमा रहना भविष्य में लाभप्रद रहेगा पर वर्तमान में भले ही कष्टप्रद हो, भविष्य में चीनी चौधराहट और अड़ोस-पड़ोस की जमीनों को हड़पने, विश्व बाजार में बढ़ते उसके कदमों से अमेरिका न केवल बौखलाया हुआ हैं और वो एक-दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं चूकना चाहते, दूसरी तरफ वह न केवल भारत की 2 लाख वर्ग कि.मी. से ज्यादा जमीन हड़प चुका है वरन् वो पूर्वोत्तर राज्यों को पूरा हड़पने के लिये 1949 से ही मंसूबे बांधा बैठा है, देर-सबेर वह इस मंसूबे को पूरा करने के लिये आक्रमण करेगा। भारत के वर्तमान कांग्रेसी भ्रष्ट, निकम्मे, अय्याश, सफेदपोश लूटेरों का ध्यान केवल लूट-खसोट पर ही लगा है। इसलिये वो जानबूझकर अंजान बने हुए हैं। 50 वर्ष में अपनी सामरिक क्षमता विकसित करने की तो दूर प्रतिरोधक क्षमतायें भी ढंग से विकसित नहीं कर पा रहे हैं। ताकि उसको मुंहतोड़ जवाब दें सकें, आक्रमण के समय अमेरिका ही साथ देगा इस दृष्टिकोण से अमेरिकी फौजों का अफगानिस्तान में जमे रहना भविष्य के लिये बेहतर रहेगा।

साप्ताहिक समय माया

दूसरों की बर्बादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था

स्वच्छंद यौनाचार से डूब रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था

भारत के धूर्तों सबक सीखो : मिश्रित अर्थव्यवस्था ही सफल

विश्व के दादा, गुंडे, आतंकवादी अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था डूब रही है। राष्ट्रपति बराक ओबामा बेशक पूर्णतः जिम्मेदार नहीं वर्तमान अमेरिकी डूबती अर्थव्यवस्था के लिये। अर्थव्यवस्था डूबने की शुरुआत 1970 के दशक से हुई, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। हर कार्य वहां पूंजी के दम पर आंका गया, यहां तक कि वहां बड़े युद्ध भी निवेश और लाभ के मूल्यांकन के दम पर हुए।

रक्तपात, युद्ध भी भावी निवेश और उस पर भविष्य में होने वाले लाभ के लिये लड़ने का सामने सीधे से उदाहरण हैं। ईराक पर सन् 2003 में आक्रमण के लिये रणनीति तैयार कर पहले उसे रासायनिक हथियारों और नाभिकीय हथियारों के विकास का आरोप लगाकर इसका तेल लूटने और उस पर मिलने वाले लाभ के आंकलन के बाद ही पूरी दुनिया में उसके विरुद्ध सन् 2001 से माहौल बनाकर उस पर आक्रमण किया गया, जिसमें अमेरिकी और नाटो राष्ट्रों की तेल और हथियार कंपनियों का पैसा लगाया गया था, वही हाल अफगानिस्तान पर आक्रमण का भी था। अमेरिका और नाटो राष्ट्रों का उद्देश्य था कि अफगानिस्तान पर आक्रमण कर और कहां पैर जमाकर दक्षिण एशिया के भूगोल की दृष्टि से एक तरफ पाकिस्तान, रूस, चीन और भारत पर भविष्य में निगाह रखने और दूसरी तरफ ईराक पर आक्रमण के बाद वहां बैठी सेनाओं अफगान में कार्यरत अमेरिकी और नाटो सेनायें ईरान को घेरकर परमाणु हथियारों के नाम पर दो तरफ से जमीनी और सामने से नौसैनिक हमलाकर कब्जा कर पेट्रोल हथियाने की रणनीति तैयार की गई थी, ईरान की समुद्री सीमा में अमेरिकी बेड़े और नौसेना ने कई बार सैन्य अभ्यास के दौरान उसे उकसाने और युद्ध छेड़ने का प्रयास भी किया परन्तु अंतरराष्ट्रीय बदनामी के डर से उस पर अमेरिकी और नाटो हमले नहीं किया जा सके यह लाखों-करोड़ अमेरिकी डालर का निवेश भी वित्तीय घाटा देने में भारी पड़ा। ऐसे पूरे विश्व में अमेरिका के कई अभियान जिसमें वियतनाम युद्ध भी शामिल है जो लगभग अमेरिका ने वियतनाम धरती पर लगभग 12वर्ष तक लड़ा, चूंकि उसके पीछे रुस का सहयोग मिलता रहा आखिर में अमेरिका वहां से भाग खड़ा हुआ, जो घाटे के बड़े आधारों में से एक हैं।

दूसरी ओर अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था में स्वच्छंद चारिता, स्कूलों में यौनाचार से अनाथ बच्चों को पालने पोसने और बड़ा करने से तो वित्तीय घाटा उठाना ही पड़ा, इसका ही दूसरा पहलू यह भी रहा कि उसकी आगे आती पीढ़ी को स्कूलों के स्वच्छंद यौनाचार ने अय्याश, निक्कमा तो बनाया ही इसके साथ ही युवा होती पीढ़ी के मस्तिष्कों को भी कुंद कर दिया,ल जिसकी रभपाई विदेशियों को बुलाकर काम करने और भुगतान डालर में करने से अमेरिकी वित्तीय व्यवस्थाओं की चूलें हिला दीं। बेशक यह अमेरिकी यह अमेरिकी वित्तीय संकट का बहुत बड़ा हिस्सा जो अमेरिकी सरकार दूसरे देशों जैसे पाकिस्तान जिनसे भविष्य में बहुत बड़ा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करने के दृष्टिकोण से बांटती है और लाभ समय पर हो नहीं पाता, उसमें भी डूब जाता है। क्योंकि अमेरिका के कुछ विश्वविद्यालयों में भावी भविष्य विश्व का और अमेरिका के लाभ प्राप्त करने के तरीकों का ही अध्ययन और अनुमान लगाकर ही दांव खेले जाते हैं। भविष्य के तो अनुमान निष्फल चले जाते हैं तो दांव 50-50 प्रतिशत की संभावनाओं पर ही चलते हैं। फिर भविष्य में कौन सा राष्ट्र क्या करेगा? और वर्तमान में क्या कर रहा है कि निगरानी, जासूसी के अभियानों में भी खर्च ही ज्यादा होता है।

डंपर का जिन्न बोतल से बाहर आने को बेताब

आईआरआई डंपर मामले का परीक्षण कर ले जाएगी उच्च न्यायालय

भोपाल। डंपर मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। जिला अदालत ने भले ही उन्हें क्लीन चिट दे दी है लेकिन देश में भ्रष्ठाचार विरोधी मुहिम के बीच अन्न हजारे की तरह काम करने वाली संस्था भारत पुर्नोत्थान अभियान (आईआरआई) अब इस मामले का परीक्षण कर हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ले जा सकती है। देश में उच्च स्तर के भ्रष्ठाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाली यह संस्था देश के उच्च पदों पर काम कर चुके लोगों ने गठित की है। रविवार को संस्था के तीन सदस्य पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदोह, पूर्व वायु सेना अध्यक्ष एस कृष्णास्वामी, केरल के पूर्व डीजीपी उपेन्द्र वर्मा राजधानी में इस मुहिम के खिलाफ जन समर्थन जुटाने आए थे। यहां एक आयोजित एक गोष्टी में डंपर मामले के बारे में उन्हें बताकर इसमें मदद मांगी गई। इन सदस्यों ने मामले से संबंधित सारे दस्तावेज मांगे हैं। संस्था के पदाधिकारी पहले मामले का परीक्षण करेंगे और इसके बाद यदि उन्हें लगता है कि वाकई में इस मामले में उच्च स्तर पर भ्रष्ठाचार हुआ है तो इसमें वे आगे की लड़ाई लड़ने में मदद देंगे।

क्या है आईआरआई

आईआरआई ने देश में उच्च स्तर पर भ्रष्ठाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है। अन्न हजारे का समर्थन करने वाली इस संस्था के सारे पदाधिकारी देश के उच्च पदों पर रहे हैं। संस्था भ्रष्ठाचार और विदेशों में जमा काला धन वापस लाने के लिए भी काम कर रही है। संस्था का मानना है कि भ्रष्ठाचार ऊपर से नीचे की तरफ चलता है और जब तक सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग भ्रष्ठाचार में लिप्त रहेंगे तब तक इस समस्या का समाधान संभव नहीं है।

कौन हैं सदस्य

जस्टिस आरसी लाहोटी पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जेएम लिंगदोह, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, वीके शुंगलु पूर्व सीएजी, एस. कृष्णास्वामी पूर्व वायुसेना अध्यक्ष, जेएफ रीबेरियो पूर्व डीजीपी, एसके जोशी पूर्व डीजी सीएसआईआर, भूले लाल पूर्व सचिव भारत सरकार, हरि गौतम पूर्व अध्यक्ष यूजीसी, एसके दुबे पूर्व निदेशक आईआईटी खरगपुर, एसपी तालुकदार पूर्व विशेष निदेशक इंटेलीजेंस ब्यूरो, एनसी सक्सेना, पूर्व सदस्य योजना आयोग, एसएटी रिजवी पूर्व सचिव भारत सरकार, जावीद चौधरी, पूर्व डीजीपी, बीआर लाल पूर्व डीजीपी, प्रो. एसजेडएच जाफरी दिल्ली विश्वविद्यालयः एसआलार लाखा अध्यक्ष लोक सेवा आयोग उप्र, वीएस पाण्डेय आईएएस, राजू शर्मा, आईएएस, जसवीर सिंह आईपीएस और सुनील कुमार आईएएस।

अब तक क्या किया

n पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त पीजे थॉमस की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सरकार को उन्हें हटाना पड़ा। केन्द्र सरकार ने थामस की नियुक्ति उनके खिलाफ चल रही जांचों, न्यायालय में चल रहे मामलों को दरकिनार करते हुए की थी। इस प्रकरण में प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से अपने निर्णय के लिए खेद प्रकट करना पड़ा। संस्था की पहली बड़ी जीत। n विदेशों में जमा काले धन एवं इससे जुड़े लोगों के खिलाफ आईआरआई के 16 सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट मे जनहित याचिका लगाई। n सबसे बड़े टैक्स चोर हसन अली और तापोरिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ठोस तथ्य रखे, दोनों आरोपी जेल में n सांसदों की खरीद-फरोख्त के मामले में दोषियों पर कार्यवाही के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सभी पक्षों को नोटिस। n काले धन को वापस लाने के लिए आईआरआई के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल बनाने के बारे में तर्क सुने गए तथा इस बारे में निर्णय सुरक्षित कर लिया है। n आईआरआई ने प्रवर्तन निदेशालय में व्याप्त भ्रष्ठाचार तथा काले धन के मामले में प्रभावी कार्यवाही न करने का मामला भी उठाया जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को जम कर फटकार लगाई। जिससे बौखलाकर प्रवर्तन निदेशालय के भ्रष्ठ अधिकारियों ने आईआरआई के सदस्यों पर झूठे आरोप लगाए। बाद में इन अफसरों को मुंह की खानी पड़ी।

आईआरआई की अपील

n देश के सर्वोच्च पदों पर काम कर चुके लोगों की यह आम राय है कि भ्रष्ठाचार ऊपर से नीचे की तरफ चलता है और जब तक सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग भ्रष्ठाचार में लिप्त रहेंगे तब तक इस समस्या का समाधान संभव नहीं है।

n वैसे भी देश के कानून के अनुसार रिश्वतखोरी कोई समस्या नहीं है बल्कि साफतौर से एक अपराध है और जो भी व्यक्ति भ्रष्ठाचार में लिप्त रहता है या रिश्वतखोरी करता है उसे देश के कानून के अनुसार दण्ड मिलना ही चाहिए।

n जरूरत इस बात की है कि सर्चोच्च पदों पर बैठ चुके या वर्तमान में उच्च पदों पर आसीन लोगों द्वारा अर्जित की गई संपत्ति के एक-एक पैसे का हिसाब देश को दिया जाए।

n भ्रष्ठाचार के अपराधी दंडित नहीं होते क्योंकि सामान्यतः दण्ड देने का अधिकार जिन लोगों को प्राप्त है,, उनमें से कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांशतः स्वयं ही दिन प्रतिदिन भ्रष्ठाचार में लिप्त हैं।

n इसी तरह वर्षों से देश की संपत्ति को अनियमित ढंग से एवं अपराधिक कृत्य करके विदेशों में धन जमा करने वाले भी हमारे राष्ट्र के दुश्मन हैं जिन्होंने 70 लाख करोड़ रूपयों से भी कहीं ज्यादा धन विदेशों में जमा कर रखा है।

n देश की इस लूटी हुई संपत्ति को वापस लाकर गरीबी और पिछड़ेपन को बिना किसी देरी के समाप्त किया जा सकता है।

n सर्वोच्च स्तरों पर व्याप्त भ्रष्ठाचार और विदेशों में जमा खरबों रुपए तभी वापस आ सकते हैं जब आम जन इसके लिए एक जुटों और इस समस्या को दूर करने के लिए अपना हर प्रकार का सहयोग व समर्थन देने के लिए आगे आए।

n इन समस्याओं को चूंकि वर्षों से समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, इसलिए इनसे लड़ने का साहस या क्षमता वर्तमान की व्यवस्था पूरी तरह से खो चुकी है।

म.प्र. जनसंपर्क भ्रष्ट डकैतों का अड्डा

भोपाल। गत कुछ माहपूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार की छवि बनाने वाले विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में विभाग के मक्कार चापलूस कर्ताधर्ताओं ने उप संचालक स्तर तक के अधिकारियों को बैठक में शामिल कराया। क्योंकि सरकार का छवि बनाने से ज्यादा यहॉ के अधिकारियों को अपने चमचों को चमकाने की ज्यादा चिंता रहती है। विभाग जाये भाड़ में । मुख्यमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल में जनसंपर्क विभाग की पहली बैठक ली तव उसमें कहा था कि काम छोटे अधिकारियों से लिया जाता है और यहॉ के बड़े-बड़े अधिकारी मजे में स्वयं ए.सी. में बैठकर भ्रष्ठाचारी सॉठ-गॉठ करते रहते है कुछ अधिकारी अय्याशी में लगे रहते है। मुख्यमंत्री जो छोटे से छोटे आदमी का दर्द जानने की कोशिश में रहते है ने विभाग के आला अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप ने उपर के पदों पर तो अपनी अपनी तरक्की के रास्ते खोल लिए और बढ़े पद हथिया लिए जबकि काम नीचे वाले लोग करते है, जिन्हें एक ही पद पर काम करते बर्षों हो गये आखिर वे सरकार की छवि बनाने में कैसे रूचि लेगें। इसी तरह उन्होंने चुनिन्दा अखबारों और उनके मालिकों तथा बड़े लोगों पर जनसंपर्क का पैसा जो जनता की गाढ़ी कमाई का है,लुटाने पर भी भलाबुरा कहा था।जबकि प्रेस के छोटे संवाददाता जो फील्ड में जाकर टेबल पर न्यूज बनाते है ,उन्हें जनसंपर्क विभाग में हमेशा दुत्कार ही मिलती है। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद विभाग में परिवर्तन भी किया गया वह भी पुरानी भ्रष्ठ परम्परानुसार । समाचार प्रभाग में एक ऐसे चापलूस अधिकारी को मुखिया बनाया गया जो स्वयं ऐसे सजे धजे कक्ष में बैठा था जैसे वह विभाग का मुखिया आयुक्त हो ।इस अधिकारी का व्यवहार ऐसा कि वह छोटे और मध्यम दर्जे के पत्रकारों से बात करने में अपनी तौहीन समझता। उसकी बोली ब्लीक न व्यवहार और रूतबे में होड़ आई.ए.एस. अधिकारी जैसी । वहीं अपने पद प्रभाव का उपयोग कर अपनी पत्नी को विज्ञापन एवं समाचार कटिंग शाखा का प्रभार दिला दिया ,ताकि अपनी पकड़ और अकड़ बनी रहे विभाग और सरकार जाये भाड़ में । जबकि पत्नी आदिम जाति कल्याण विभाग की शिक्षिका है जिसे प्रतिनियुक्ति पर जन्सम्पर्क विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों जिन्हें वर्षों का विभाग में कार्य करने का अनुभव है से ज्यादा रूतबा और सुविधाऐं इस अधिकारी ने विगाग को अपनी बपौती समझ कर दिला रखी है। इस अधिकारी ने अपने कुछ परिचित पत्रकारों से पत्नी के नाम से लेख लिखवायें और मुख्यमंत्री एवं विभाग के मंत्री श्री लक्ष्मी कान्त शर्मा को खूब प्रभावित कराया परन्तु काम का प्रभाव कहीं नजर नहीं आया ,हालांकि इस महती भूमिका में संयुक्त संचालक श्री मंगला मिश्रा का भरपूर सहयोग रहा है। वहीं आयुक्त को भी अपने इन्दौर के कार्यकाल के रूतवे से मुटठी मे करने का प्रयास किया है और वहुत कुछ सफलता भी मिली। अब यक्ष प्रश्न यही है कि ऐसे कैसे जनसंपर्क विभाग जहां उसकी स्वयं की छवि भ्रष्ठाचार में आकण्ड डूबी है वह सरकार की छवि को जनता के बीच कैसे चमकायेगा। शायद इसी लिए दुःखी मन से मुख्यमंत्री ने बैठक में विभाग को बन्द करने की मंशा जाहिर की थी । असल में उन्हें यह योजना अमल में लानी चाहिए कि वे इन ऊपर के अधिकारियों को जिलों के कार्य की भी जबावदारी सौपें ताकि यहॉ की राजनीति और कूटनीतिक चालों पर रोक लग सके और विभाग ब्लीक ढंग से कार्य कर सके । मध्य प्रदेश सन्देश पर भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की थी। यहॉ जिस अधिकारी को सूझ थी दृष्ठि थी उसे बदल दिया गया और जबकि नीचे का अधिकारी जो छपाई से लेकर मैटर तक लाता है वह अभी भी वहीं है। वाह भई वाह इसे कहते है दबंग विभाग अर्थात जनसंपर्क विभाग जिसकी सरकार को मुखिया मुख्य मंत्री क ी भावनाओं को रौदने का लायसेंस प्राप्त हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा मीडियाकर्मियों का वेतन तय कर सकती है सरकार

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि सरकार समाचार पत्रों, एजेंसियों तथा दृश्य मीडिया के श्रमजीवी पत्रकारों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण पर मजीठिया आयोग की सिफारिशें लागू करने पर निर्णय ले सकती है. न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने यह निर्णय दिया. इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि यह मामला न्यायालय के विधाराधीन होने की वजह से वह इन सिफारिशों पर निर्णय नहीं ले सकती. न्यायालय ने हालांकि यह भी कहा कि आयोग की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय इसे चुनौती देने वाली समाचार पत्रों तथा एजेंसियों की याचिकाओं की सुनवाई के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा. आनंद बाजार पत्रिका, टाइम्स ऑफ इंडिया और कई समाचार एजेंसियों ने सर्वोच्च न्यायालय में आयोग की सिफारिशों को चुनौती दी है. मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को करेगी. मजीठिया आयोग ने समाचार पत्र, एजेंसियों, टेलीविजन के श्रमजीवी पत्रकारों और अन्य कर्मचारियों के वेतन में कई गुना वृद्धि की सिफारिश की है.

वाणिज्य कर कदम-कदम पर भ्रष्टाचार और जालसाजियां

भ्रष्टों को पदोन्नतियां व्यापारियों को लूट की पूरी छूट

म.प्र वाणिज्य कर के इंदौर स्थित मुख्यालय भोपाल स्थित मंत्रालय में चारों तरफ भ्रष्टाचार और जालसाजीयों का बोलबाला है। भ्रष्टों और जालसाजों जिसमें मंत्री राघव जी का विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी जो पूरे म. प्र वाणिज्य कर में पदोन्नतियों स्थानांतरण और आरडी डो कि वाणिज्य कराधिकाारी के रूप में मंत्री राघव जी के यहां गया था तीन चार वर्ष में ही उपायुक्त के पद पर पदोन्नत हो गया जबकि उसके पूर्व से बैठे अनेको सहायक आयुक्त उपायुक्त बनने के इंतजार में है। इसी प्रकार सहा आयुक्त आर पी श्रीवास्तव जो मुख्यालय पर ही 10 वर्षो से ज्यादा वर्षो से जमे रहकर भ्रष्टाचार और जालसाजिया करते रहेंगे। पद्दोन्नत होकर अनेको को पीछे छोड़ते हुए जालसाजी पूर्ण तरीके से उपायुक्त बना दिये गये

अभी सहायक वाणिज्य कराधिकारी से वा.क.अ. और वा.क. अ से सहायक आयुक्त की पदोन्नतियों की भी एक बड़ी सूची जारी होना है उसमें भी ऐसे कोई भ्रष्टाचार हुए हैं। कई वरिष्ठ पीछे हो गए हैं। और कनिष्ठ लूटो और लुटाओ के दम पर पदोन्नतियां प्राप्त कर लेंगे। वाणिज्य कर मुख्यालय से लेकर नीचे तक छोटे शहरों के वाणिज्य कर कार्यालय में इसे लेकर काफी शेष हो पर सब वास्तविकता सूची के आने के इंतजार में है और कमर कसे बैठे हैं। कि मामलों को न्यायालयों तक ले जाएंगे अब प्रश्न यह उठता है कि जब उच्च स्तर पर भी जालसाजियां और भ्रष्टाचार किया जाता है और लेन देन के दम पर ही सारे कार्य यथा पदोन्नतियां पद स्थापनायें की जाती है तो फिर इंडियन एव्युसिंग सर्विस के अधिकारी यथा आयुक्त शैलेन्द्र सिंह अपने कमरे में बुलाकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों जो अतिरिक्त आयुक्तों जो संख्या में न और उपायुक्त ने भी 8-10 थे 26-27 जुलाई 11 को जब आयुक्त सभा कर रहे थे। घुसे तो अचानक बधाई देन की अपेक्षा सनक उठे और अधिकारियों को गलियाते हुए बोले सब भ्रष्ट हो निकम्मे हो चरित्रहींन हो सब के चेहरे उतर गए और कोई कुछ न बोल सका आयुक्त प्रधान सचिव अपर सचिव पीसी राठौर यादव जालसाजियां करें फाइलें गायब करें तो सब पुण्य और छोटे करें तो भ्रष्ट निकंमें और चरित्रहीन 1 जून 11 को पी एस को सूचना के अधिकार में पत्र भेजा 5 जून को मोबाईल पर पूछना कि पत्र मिला तो बताया गया नहीं मिला 8 जून को उसकी फोटो कापी भेजी तो 10 को ही मिल गई।

जब 10 जुलाई को उसकी फोटो कांपी भेजी गई तो 1 जुलाई को जुलाई को उसकी भूल भी मिल गई। जिसकी प्रविष्टी एक जुलाई की तारीख में की गई। जानकारी दी गई कि एक विशेष फाईल में उस भ्रष्ट अधिकारी को पैसे के दम पर बचाने और पदोन्नत करने की तैयारी चल रही थी। अर्थात ये कहें कि पुण्य छोटे अधिकारी करें तो पाप भ्रष्ट निकम्मे और चरित्रहीन

एक तरफ तो इसी आयुक्त ने वाणिज्य करो के प्रकरणों की स्वनिधी की प्रक्रिया में लाकर व्यापारीयों उनके दलालों वकीलों के खुली जालसाजीयां करने की छूट देकर पिछले दो वर्ष में ही लगभग रु 2 से 3000 करोड़ की पिछले 15-17 वर्षो के वाणिज्य कर वसूली लाखों में शासन का कम से कम रु. 2000 करोड़ से ज्यादा अटका था फिर वेट लगने के बाद एक तरफ तो शासन हर वर्ष बजट में करो के बाद एक तरफ तो शासन हर वर्ष बजट में करो की घोषणायें कर जनता से व्यापारी वसूली तो बजट से घोषित दरों से करता है फिर आयुक्त महोदय उन्हें स्वकर निर्धारण की 99 प्रतिशत करोड़ में जायेगा हजम करने की भी छूट देता है एक तरफ व्यापारी को लूट की पूरी छूट देता है।

दूसरी तरफ जितना भरना है उतना भरों यह कह कर उन्हें न केवल वर्तमान में भ्रष्ट बना रहा है। वरन भविष्य में भी लूट की छूट के साथ उन्हें कर चोरी भी सिखाता है। ताकि खाते में हेरा फेरी कर 10 से 20 प्रतिशत भी कर न भरें जब सख्ती से वसूला जाता था तो 40 प्रतिशत से ज्यादा वसूली नहीं होती थी।

तो अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिर न क्रांस चेक न खातों की जांच की व्यवस्था जहां तक अकेक्षण विभाग की सवाल है तो पिछले तीन वर्ष की उपलब्धियां है। एंटी इवेजन के हरामखोरों को सूचना के अधिकार में जालसाजी से छूट की व्यवस्था भी जालसाजियां लूट और वसूली की खुलासा न हो सके इसलिए ही करवाई गई है।

एक तरफ छूट दी जाती है। दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत भी 13 प्रतीशत वेट मोबाईल रिचार्जो पर थोपा जाता है। 5 प्रतीशत कर शक्कर और कपड़े पर अगस्त के महीने से थोपा जाता है। अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुसार आयुक्त सनकायुक्त हो गए हैं। कब कहां कैसे सनक सवार हो जाएगी और जब स्तकर निर्धारण की छूट है तो व्यापारी अपना टर्नओवर घटाकर ही कर जमा करेगा।

फिर अगर आयुक्त ईमानदार थे तो कम्प्यूटर खरीदी में रु. 30000 का कंम्प्यूटर 2 लाख में क्यों खरीदे गए। जब शासकीय साफ्टवेयर कंपनी के साफ्टवेयर न केवल सस्ता वरन सुचारू सेवाये दे रहा था और सफलता के साथ काम कर रहा था तो टाटा कंसलटेंसी से साफ्टवेयर नया क्यों बनवाया गया। चार गुनी कीमत पर जो कि अभी भी ढंग से नहीं चल रहा है। जब कि टाटा ने् न केवल जालसाज वरन आतंकवादियों को पैसा बांटकर राष्ट्रद्रोह का काम भी कर रहा है। वह बेशक मोटा कमीशन बांटकर ही काम साधता है। जो कि सिंगूर नैनों प्लाट के मामले में सिद्ध हो गया है। किन्तु आईएएस तो जालसाज कंपनियों रिलायंस टाटा जैसों की कठपुतलियां है। जो कि मोटे कमीशन के लिए ही उनके तलवे चाटते हैं।

रु. ५० – १०० के स्टांप क्यों नही मिल रहे

इंदौर मे 6 माह से कोषालय पंजीयक को चाहिये मोटी महीना वसूली

डकैतों के अड्डे बन गए चुके हैं पंजीयक कोषालय

इंदौर में पिछले 6 माह से ज्यादा समय से पूरे नगर के 300 से ज्यादा गैर न्यायिक मुद्रांत विक्रेताओं के पास रु. 50 और 100 की कीमत के मुद्रांको का अभाव है तब कि शपथ पत्र नोटरी मुख्त्यार नामा आदि कार्यो में इनकी भारी माग होती है। इसके विपरीत यह कृत्रिम अभाव बनाने में जिला कोषालय के साथ ही जिला पंजीयक और संयुक्त संचालक पंजीयन एवं मुद्रांक की नकारात्मक और संयुक्त संचालक पंजीयन एवं मुद्रांक विक्रेताओं 2 से 5000 प्रति माह चाहिये अर्थात मुद्रांको की कालाबाजारी में इन हरामखोरों की ही बड़ी भूमिका रहती है। क्यों कि यदि मुद्रांत विक्रेता अपने कमीशन में से इन हराम खोरों को रु 2000 से 5000 रु महीना देगा तो तो कोई वह करोड़ों रु का कारोबार तो कर नहीं सकता कि जिसे कमीशन में ही लाख दो लाख प्रतिमाह की कमाई हो जाएगी।

दूसरी ओर पंजीयक महानिरीक्षक कार्यालय से फोन पर बातचीत की गई तो मालूम पड़ा कि जिला कोषालय स्वयं ही मुद्रांक रु 50 से 100 के नहीं उठा रहा है। जब जिला कोषालय अधिकारी स्वाती त्रिपाठी से इस संबंध में चर्चा करने के लिए फड़निश कांम्पलेक्स स्थित कार्यालय में मिलने और स्थिती जानने का प्रयास किया तो मेडम मीटिंग में व्यस्त हैं कहकर टाल दिया गया वर्तमान में जिला कोषालयों चाहे तो इंदौर धार देवास उज्जन पूरे मप्र के सभी कोषालयों की स्थिती यह है कि जहां बैठे चपरासी बाबुओं कम्प्यूटर आपरेटर से लेकर बड़ा बाबू कार्यालय अधिक्षक सहायक कोषालय अधिकारी कोषालय अधिकारी को हर कार्य के पैसे भुगतान की कीमत के अनुसार चाहिए बिना दान के यहां कोई काम नहीं होता यहां तक की इन शूकरों की फौज को दैनिक वेतन भोगी कार्मचारियों के वेतन के चेक में से भी प्रति चेक रु 300 से 500 रु चाहिये यही कारण है कि प्रदेश के सभी कर्यालयों में वेतन भुगतान से पहले उस विभाग के बाबू को सबसे रु 20 से 50 तक चेक लाने के लिए इकट्ठे करने पड़ते हैं।

ताकि 500 से 1000 तक का भुगतान कोषालय अधिकारीयों के कर्मचारियों तक कर चेक को अधिकारी कर्मचारियों के बैंक खाते में जमाकर सके. यही हाल यात्रा चिकित्सा महंगाई आदि भत्तों के कुल राशि के 1 से 5 प्रतिशत तक हो जाता है पेंशन खातों में इस शूकरों की स्थिती और ज्यादा मोटी वसूली हो जाती है। छठे वेतनमान के भुगतान में भुगतान की किश्तों में प्रति कर्मचारी अधिकारी रु 500 से 5000 तक वसूले जाते हैं। नही तो बहानों का अंबार लगा देते हैं। अब जब कि सभी ठेकेदारों आपूर्ति कर्ताओं के भुगतान भी आनलाईन होने लगे हैं अब इन डकैतो ं को रु 100 से 1000 तक चाहिए होते हैं। वरना सर्वर बंद बिल त्रुटी पूर्ण है कमी है । इस प्रकार भुगतान अटकाए जाते हैं तो मुद्रांक विक्रेताओं के साथ वसूली और रु 50 से 100 के मुद्रांक इंदौर में लाकर न बेचने का कारण समझा जा सकता है।

यही हाल डकैती का पंजीयन कार्यालय में ही यहां चपरासी को भी सील लगाने के रू 100 से लेकर 500 जमीन मकान की रसीद बिक्री और कीमत के हिसाब से वसूलते हैं यहां के उपपंजीयकों से लेकर जिला पंचायत और इंदौर में बैठा श्रीकांत पांडे जिसे इंदौर में 3 वर्ष से ज्यादा हे चुके हैं। इस हरामखोर की नाक के नीचे अरबों रु की मुद्रकों के शुल्क की चोट पहंचाकर कारोबार हो रहा है। स्वभाविक है कि इसका भी हिस्सा है इसलिये इतनी सारी जांचे जालसाजी के प्रकरण में वर्षो बाद भी कुछ नहीं हो सका है। हालात यह है कि एक एक पंजीयक रु 5 लाख से लेकर रु 25 लाख तक की अवैध वसूली कर आंख मींचकर जमीनों मकानों दुकानों की रजिस्ट्रीयां की जा रही है। एक दो बार लोकायुक्तों को समय से 7 के बीच यहां छरे मारना चाहिये और चपरासियों बाबुओं से लेकर उपपंजीयक पंजीयक सुयुक्त पंजीयक पर छापे की कार्यवाही की जानी चाहिए जिस दिन भी भीड़ भाड़ ज्यादा हो मुद्रांको के संबंध में जब सं पं. श्रीकांत से बात की गई और मुद्रांक बताने के लिए कोई औचित्त पूर्ण रास्ता खोजने की बात की गई तो हरामखोर फोन पर बोलता है कि आप सिखाइये मत और बत्तमीजी पूर्ण तरीके से डांटकर फोन काय दिया शायद पद पाकर विभाग को अपने बाप की जागीर समझने लगते हैं। इन डकैतों का काफिला नियम कानून सब इनकी जेब में होता है। जनता जितनी परेशान होगी उतनी ज्यादा वसूली होगी।

चमत्कार नहीं भ्रष्टाचार बढ़ेगा लोकपाल कानून से

पेज 1 का शेष

सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत जब तक जनता या उसके प्रतिनिधी के हाथ में किसी लोकसेवक के विरूद्ध ठोस आधार व सबूत नहीं है तो कैसे सिद्ध करोगे। कहोगे कि अमूक भ्रष्ट है। पर सरकार ने ही क्या किया न केवल केन्द्र ने वरन राज्यों ने भी अपने खास चुनिंदा भ्रष्ट लोगों को बिठा दिया, म.प्र मे ही देखे जो पुराने सेवानिवृत्त भ्रष्ट इंडियन एव्युसिंग अधिकारी जैसे हरामखोर पीपी तिवारी, श्रीवास्तव, इकबाल अहमद, सेवानिवृत्त क्राइम प्रोटेक्शन सर्विश अधिकारी, दिनेश जुगरान जैसे निकम्मे शूकरों की फौज बैठा दी गई थी।

यही हाल पूरे देश में सूचना के अधिकार के आयोग में किया गया रू. पांच से दस हजार की व्यवस्था काजिए और आसानी से कोई भी अपील में त्रुटी देखकर उसके आधार पर अपील खारिज कर दी जाएगी। पिछले कार्य न ही केन्द्र सरकार ने अपने राज्यों में आयुक्तो की नियुक्तियां न राज्यों ने न कि पूरा स्टाफ मुख्यालय में भी नहीं बिठाया वरन कानून के प्रावधानों के अंतर्गत भी संभागों पर 5 वर्ष बाद भी आयुक्तों की नियुक्ति नही की गई।

दूसरी ओर सू.अ.अधि.05 की धारा 4 और उसके 17 बिन्दुओं की जानकारी देने में स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय में भी कानून लागू होने के 6 वर्ष बाद भी पूरी जानकारी इंटरनेट साइटों पर नहीं चढ़ाई गई। साथ ही इसके साथ ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कार्यालय से लेकर आयकर, केंद्रीय आबकारी जैसे जनता से जुड़े हुए विभागों से लेकर न केवल केन्द्र के वरन राज्यों के भी विभागों ने साइटें 6 वर्ष बाद भी जानकारी नहीं डाली गई, जबकि यह एक मात्र कानून ही भ्रष्टाचार की जड़ों को उखाड़ सकता है। इसके विपरीत महाभ्रष्ट न्यायालयीन व्यवस्था ने सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तहसील और जिला न्यायालयों ने इस कानून को लेकर अपने ही कानून बना दिये, वे कभी सूचना के अधिकार में किसी को कोई जानकारी नहीं देते, ये कानून मानने के लिए बाध्य नहीं, कानून इनकी रखैल है। इन्हें जनता से वसूलें गये करों से वेतन नहीं मिलता, आखिर ये क्यों करेंगे सूचना के अधिकार का पालन, आखिर अन्ना उसके समर्थकों ने क्यों नहीं आंदोलन किया।

अन्ना के लोकपाल बिल की 4 महीने तक चली लंबी लड़ाई में सरकार ने भरपूर फायदा उठाया और उसकी आड़ में 5 साल से लंबित खाद्य सुरक्षा और मानक अधि. लागू कर दिया। 5 अगस्त 11 से जिससे 5 करोड़ बेरोजगार हो जायेंगे और पैकिंग की आड़ में रिलायंस फ्रेश सबकुछ मिलावटी पैक करके ही बेचेगा, दूसरी तरफ एक गरीब जो 100 रु. प्रतिदिन कमाकर 1 किलो आटा, 100 ग्राम दाल, 10 रु. का धनिया, मिर्ची खरीदकर शाम को अपने परिवार की भूख मिटाकर चैन से खा-पीकर सोता है। वह कैसे इन रिलायंस फ्रेश में खरीदी करेगा।

क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत हर गली मोहल्ले से लेकर गांवों तक की सारी दुकानें साप्ताहिक हाट बाजार से लेकर कृषि उपज मंडियों, सब्जी मंडियों तक को पूरा समाप्त करने की योजना है। ताकि खाद्य पदार्थों पर एकमात्र रिलायंस का एकाधिकार हो और उससे राज्य की सरकारों से लेकर केन्द्र के गिद्ध सत्ताधीश मंत्रियों को हजारों करोड़ रु. में महीना मिलता रहे, इसके बारे में अन्ना को या तो कुछ पता नहीं था फिर अन्ना जो कि रा.कां.पा. शरद पंवार का समर्थक माना जाता है, और शरद पंवार अंबानी बंधुओं की कठपुतली शायद यह आंदोलन इसीलिये किया गया और अप्रैल से अगस्त 11 तक खींचा गया ताकि यह दमनकारी ईस्ट इंडिया वाला रिलायंस का कानून खाद्य सुरक्षा और मानक अधि. 06 को आसानी से लागू किया जा सके, इस राष्ट्र की आधारशिला थी मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे विश्व व्यापार संगठन ने मोटा धन बांटकर और सत्ताधीशों को लूट का खून उनकी दाढ़ों में लगाकर शुद्ध पूंजीवाद की तरफ धकेलना शुरू कर दिया, जिसे अन्ना जैसे आंदोलन ही बदल सकते हैं।

इसके अंतर्गत सार्वजनिक सड़कों पर जिन पर आत्यधिक यातायात का दबाव रहता है, केन्द्र ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाकर देश की 70,000 कि.मी. सड़कों को ठेके पर सौंप दिया वहीं राज्यों ने भी सड़क विकास प्राधिकरण बनाकर राज्यों के राजमार्गों के 5 लाख कि.मी. सड़कों को ठेकेदारों को सौंप दिया। अब सड़कें कैसी भी हों, ठेकेदार को वसूली से काम, अन्ना का आंदोलन चाहता है। बिजली कं. की लूट और रखरखाव का केवल दिखावा, दिनोंदिन देश के राज्यों के बर्बाद होते विद्युत मंडल, शिक्षा उपकर के नाम पर 2% उपकर 1987 से सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिये 2%, सभी सेवाओं, पेट्रोल की जल गैस पर उपकर, फिर भी सड़कों पर डकैती, इन सबके विरुद्ध अन्ना का आंदोलन चाहिये, वरना पूंजीपतियों ने देश के साधनों को अपना गिरवी बनाकर जनता का खून चूसना शुरू कर दिया है। यहां पर आंदोलन की सख्त जरूरत है।

साप्ताहिक समय माया

जल प्रबंधन लो. स्वा. यांत्रिकी तो निर्माण कार्यों में लो नि वि क्यों नहीं?

प्राधिकरण नगर पालिकाएं और निगम भ्रष्ट डकैतों के अड्डे

अरबों रुपये की बर्बादी पर कोई नियंत्रण नहीं, बस जनता से वसूली हो

म.प्र के साथ पुरे देश के नगरीय निकायों यथा नगर निगम व पालिकाओं में बैठे अधिकांश अधिकारी कर्मचारियों जिसमें इंजीनियर डॉक्टर रसायनज्ञों तक की भर्ती नेताओं पार्षदों और महापौरों की मर्जी और इशारों पर होती है। इनकी कोई खास परीक्षा वगैरह नहीं होती इनमें बैठे अधिकांश इंजीनियरों रसायनज्ञों आदि डो कि प्रकृति से मक्कार और कामचोर खींच तान करके डिग्रीयां हासिल कर लेते हैं। संबंधो और पहुंच के माध्यम से यहां नौकरियां पा जाते हैं । इसके बाद का हाल तो यहां की जनता देख ही रही है। नगर निगम इंदौर का नगर अभियंता हरभजन सिंह, हंश कुमार, पंधाने, जादौन, नगर स्वास्थ्य विभाग का प्रभारी डॉ राजेश कोठारी जिसके बारे आये दिन समाचार पत्रों में इन हरामखोरों की हरामखोरी की धूर्तता जालसाजियों के चर्चे होते रहते हैं। नगर प्रधिकरणों नगर निगमों पालिकाओं जैसे नगरीय निकायों में नियुक्त किये गए इंजीनियरों डॉक्टरों रासायनज्ञों आदि उंचे पदों से लेकर बाबुओं तक की नियुक्तियां आखिर लोकसेवा आयोग चयन सेवा आयोग सुपात्रों की परीक्षा लेकर शासन के नियमों के अधीन नियमित रूप से क्यो नहीं करता दूसरा तो इनमें बैठे् अजगरों की फौज तो न्यूनतम करोड़ पति होती हैं। नियमित रूप से उनके तीन वर्ष और पांच वर्ष बाद 300 किमी से दूर क्यों नहीं स्थानांतरित किये जाते ताकि क्षेत्रीयवाद के भ्रष्टाचार और क्षेत्रीय नेताओं पार्षदों के प्रभात से कर्मचारी अधिकारी इंजीनियरर्स डॉक्टर न केवल मुक्त रह सकें और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगा सकें। और नियंत्रण लगा रहे क्षेत्रीय नेताओं और जनता के साथ संबंधों के आधार पर किसी भी अधिकारी कर्मचारी पर दबाव बनाया जा सके दूसरी ओर जल जलापूर्ती और निकासी के लिए लोक स्वा. यात्रिकीय विभाग की सेवाएं और उनके इंजीनियर्स रसायनज्ञ अपनी देख रेख में काम करते है और करवाते हैं। तो प्रति वर्ष सड़कों पर खर्च होने वाले अरबों रुपये के कार्य में लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स की देख रेख में कार्य मप्र शासन के कार्य विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से गुणवत्ता और गारंटी युक्त क्यों नहीं करवाया जाता वहीं हाल निगम के निर्माण विभाग भवन अनुज्ञा नये भवनो निर्माण के साथ ही अनकी सरीक निगरानी में करवाया जाना चाहिए और गुणवत्ता हीन होने पर न केवल निगम इंजीनियर वरन लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को भी दोषी ठहराया जा सके यहीं हाल निगम प्राधिकरणों तथा तथा इंदौर विकास प्राधिकरण ग्वालियर देवास उज्जैन भोपाल जैसे 25 से ज्यादा प्राधिकरणों में होना चाहिये। बेशक मप्र लोकस्वास्थ्य यांत्रिकीय इंजीनियर चाहे वो धर्मेन्द्र वर्मा सुधीर सक्सेना संतोष श्रीवास्तव व अन्य फौज ने घोटाले नहीं किये हो एसा नहीं है। ताजे उदाहरणों में रु. 400 करोड़ से ज्यादा की सीवरेज लाईन प्रोजेक्ट में निगम इंजीनियरों औव लोक स्वा यांत्रिकी के इंजीनियरों ने जो अरबों रु के घोटाले किये उसमें एक सीवरेज लाईन पूरे शहर में बिछाई जानी चाहिए थी साथ ही एक स्टार्म वाटर लाईन जो बरसाती पानी के तूफानी बोझ को तत्काल नालों में प्रवाहित कर देती इन हरामखोरों ने तो सीवरेज लाईन कहीं कहीं डाली पर सभी मुख्य मार्गो पर इन धूर्तो ने सीवरेज के करीब रु या करोड़ो हजम कर हर जगह सार्म लाईन डाल कर इति श्री करने की तैयारी में है। छोटी मोटी सीवरेज लाईन के कनेक्शन उसमें जोड़े जा रहे हैं। तकि इस भ्रष्टाचार की हरामखोरी का पता किसी को न चल सके और अरबों रु हजम। वही हाल द्वितीय तृतीय चरण की नर्मदा लाईन का भी हुआ प्रथण चरण की तीस वर्ष पुरानी लाईनों में ही द्वितीय चरण की लाईनें और तृतीय चरण की लाइनें जोड़ दी गई। जब कि हर चरण की पाईप लाईनों को अलग अलग निपटाया जाना चाहिए था। पर उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार और कमाई और वसूली के चलते जानबूझकर तृतीय चरण की पाईप लाईनों को बाईपास से लाकर प्रथम चरण और द्वितीय चरण में जोड़ दिया गया। बाईपास से तृतीय चरण को लाने का उद्देश्य ही था कि वहां बहुराष्ट्रीय जालसाज भूमाफियाओं ने जो लगभग 400 कालोनियां काटी उन्हें सर्वप्रथम तृतीय चरण का लाभ पहुंचा कर अरबों रु की वसूली में भोपाल से लेकर इंदौर के कलेक्टर कमीश्नर महापौर तक के हिस्सेदारी की जिसकी खबरें कानोकांन किसी को न हो सकी इसके दम पर उन माफियाओं ने भी अरबों रु की वसूली जनता से कर डाली। चूकिं समाचार पत्रों जिसमें नई दुनिया दैनिक भास्कर राजएक्सप्रेस पत्रिका जैसों को वर्षों से पूरे पूरे पेज के विज्ञापन मिल रहे हैं। तो किसी ने भी अरबों रु की इन जालसाजियों पर एख लाईन भी नहीं छापी। यदि तृतीय चरण का पानी ग्रहण क्षेत्र में अतितृष्टिया ओंकारेश्वर बांध से पानी छोड़ने पर कचरा फंस गया जल्द से जल्द जल ग्रहण नहीं किया जा सका तो प्रथम द्वितीय के चरण के जल ग्रहण तो चालू थे वह जल कहां चला गया। उस जल की आपूर्ती क्या फैक्ट्री उद्योगों और विशेष क्षेत्रों को उपकृत करने बाद दी गई। इस मामले में भी उच्च न्यायालय और लोकायुक्त जॉच का मुद्दा बनाया जाना चाहिये। सेवानिवृत इंजीनियरों को सजा देनी चाहिए।

प्रोजेक्ट उदय में दो अरब के कचरा प्रबंधन का माल कहां गायब हो गया खरीदी 50 से 100 प्रतिशत पर की गई

म.प्र के भोपाल ग्वालियर इंदौर जबलपुर में प्रोजेक्ट उदय के अंतर्गत एडीबी के अंतर्गत रु 15 अरब से ज्यादा के रिक्शे जो घर घर से कचरा उठाने से लेकर कचरा गाड़ियों नालियों को साफ करने से सक्शन ट्रक जो रु 80 लाख रु के थे कचरे के कंटेनर्स को उठाने वाले तीन चार प्रकार के ट्रक कचरा के डिब्बों में अरबों रुपये की खरीदी की गई थी। सन 06-07 में यहां तक रिक्शे जिनमें 6 से 8 प्लास्टिक के डिब्बे लगे थे जिनका वास्तविक बाजार मूल्य उस समय मात्र रु 10 से 12 हजार रु अधिकतम अकेले इंदौर में ही लग गया 500 से ज्यादा रिक्शों को आवंटन किया गया था किसी का भी पता नहीं है। ठेले की गाड़ियां जिनसे कचरा इकट्ठा कर गाड़ियों में संग्रहण करना था न तो सफाई कर्मियों के पास नगर निगमों में वो गाड़ियां दिखती है। स्वाभाविक है कि सफाई कर्मी कचरे को अपने स्तर पर ढेर लगाकर येनकेन प्रकरण इकट्ठा कर कंटेनरों में भरते हैं। इसके विपरीत व्यापारियों रहवासियों पर प्रदूषण के नाम पर रू 1-1 हजार के चालान काट दिये गये जो स्पष्टतः गैर कानूनी थे। क्यों कि कचरा प्रबंधन के अतंर्गत जो कि नगर निगम के सफाईकर्मियों को हर दुकान और घर घर जाकर कचरा गाड़ियों में कचरा इकट्ठा करना था नगर निगम के भ्रष्टहरामखोर डकैतों ने अपने कुकर्मो को तो जनता को बताया नहीं और स्वयं महापौर मोघे अपनी बहादुरी का झंडा लहराने निकल पड़े और सड़क पर कचरा फेंकने वालों के चालान स्वयं ने बनाये।

मप्र भाजपा– हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे

मप्र के 15 डकैत रा.प्र.से. से हुये भा.प्र.से.

खुला खेल लूटो और पांच करोड़ लुटाओ, आई ए एस बन जाओ

म प्र भाजपा के शिवराज से लेकर पूरी मंत्री परिषद जिसमें वित्त मंत्री राघव जी से लेकर अजय विश्नोई अनूप मिश्रा अर्चना चिटनिस बाबूलाल गौर ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह बिसेन गौरी शंकर बिसेन गोपाल भार्गव हरिशंकर खटीक जगन्नाथ सिंह जगदीश देवड़ा जयंत मलैया लक्ष्मीकांत महेन्द्र हार्डिया मनोहर उंटवाल नागेन्द्र सिंह नरोत्तम मिश्रा पारस जैन एस एन कुशवाह रंजना बघेल राजेन्द्र शुक्ला रामकृष्ण कुसमारिया रंजना बघेल सरताज सिंह तुकोजीराव जी पवांर उमाशंकर गुप्ता से विजय शाह तक महाधूर्त जालसाज भ्रष्ट गिद्दों की फौज बैठी से जिसकी मांग एक सूत्रिय कार्यक्रम है। जहां से जैसे हो लूटो और हमें लुटाओ सारे हराम खोरों को जैसे मौंका मिलता है वहां अपनी जालसाजियों और लूट के करिश्में दिखाने से बाज नहीं आते जब इन्हे वैध अवैध कार्यो के लिये वसूली चाहिये तो फिर कैसे तो फिर कैसे उम्मीद की जा सकती है कि इनके अंतर्गत कार्य कर रहे नौकर शाह इनकी कैसे सुनेंगे सब को मालूम है कि आखिर लूटना लुटाना ही प्रशासन है। तो इन अक्ल शक्ल के पैदलों की जिनकी औकात 5 वर्ष से अधिक नहीं है तो वे अपनी लूट और वसूली का भविष्य सुरक्षित रखते हुए कुछ टुकड़ों की झूठन इन्हें भी डाल देते हैं। आखिर कोई भी नेता मंत्री देश की सेवा करने तो नहीं आया, आये देश और जनता की सेवा के नाम पर उनका मेवा बटोर कर अपना और अपनी आने वाली पीढ़ीयों का कल्याण करने ही है सबके अपने पुराने इतिहास हैं जिसकों जहां मौका मिल रहा है हांथ आजमा रहा है। चाहे वह स्थानांतरण पर स्थापना हो पदोन्नति हो भ्रष्टाचार की जांच रुकवानी हो मलाईदार पद चाहिये हो कमाई चाहिये हो हर कदम लुटाओ और लूटो यह सत्ताधीशों का प्रथम ध्येय होता है।

इसके लिए वो परम भ्रष्ट को जिन्होंने कदम कदम पर जाल साजियां भ्रष्टाचार लूट वसूली की हो जिनके ऊपर अनेकों जांचे चल रही हों उन्हें आईएस बना दिया गया उन 15 में से एक महत्वपूर्ण जालसाज भ्रष्ट आशुतोष अवस्थी भी था जिसकी हाल ही में मप्र उच्च न्यायालय इंदौर शाखा ने दूसरी बार भ्रष्टाचार की जांच को रोके जाने की द्विसदस्यीय न्यायधीशों ने याचिका खारिज की है। इस याचिका में एक याचिका कर्ता मप्र लोक स्वा यात्रिकीय के प्रमुख अभियंता सलाहकार गुमान सिंह अमोर भी था। जो वर्तमान में पूरे प्रदेश का कार्यभार लूटो और लुटाओ के दम पर संभाले हुए हैं । जिस पर पांच हत्याओं के केस लदे और सब में पैसे देकर बेदाग बरी हो गया। की भी लोकायुक्त की विभागीय जांच रोकने की प्रक्रिया को द्विसदस्यीय न्यायधीशों ने खारिज किया है।

ऐसे ही जिला पंचायत के पूर्व सी ई ओ महेशचंद्र चौधरी जो वर्तमान में आयुक्त नगर निगम उज्जैन हैं। वो भी न केवल ग्रामीण विकास के धन में कदम कदम पर वसूली से लेकर मनरेगा में भी जमकर न केवल वसूली की वरन मनरेगा में संविदा में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारियों का भ्रष्टाचार कर चयन देने के लिये मजबूर किया जिन्होंने भ्रष्टाचार कर धन चौधरी के चरणो में समर्पित किया उन्ही का कार्यकाल बढ़ाया गया, फिर भी जानबूझ कर उन्हें घटे वेतनमान का आदेश होने के विरूद्ध भी लाभ नहीं दिया गया।

पाठकों को बता दें कि राज्य प्रशासानिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा मे जाने के लिए खुली 5 करोड़ की सौदेबाजी होता है जो रुपये 5 करोड़ खर्च करता है उसे ही भारतीय प्रशासनिक सेवा का लाभ मिलता है। सूत्रों के मुतालिक तो रु एक करोड़ तो समान्य प्रशासन विभाग में औपचारिकताएं पूर्ण कर फाईल पर प्रशंसा लिख कर फाईल आगे बढ़ाई जाती है। फिर मंत्री सामान्य प्रशासन भी एक करोड़ रुपये हजम करता है। फिर आगे पढ़कर प्रमुख सचिव और मुख्य मंत्री से आगे बढ़ते हुए दिल्ली पहुंचती है। रु. दो से तीन करोड़ का खेल वहां होता है। इसके बाद आईएएस बनाया जाता है। अर्थात 15 आईएएस बनाए गए रु 75 करोड़ का जो धन बांटा गया स्वभाविक है कि हरामखोंरो ने जनता के धन से ही कमाया और बांटा

स्वच्छ प्रशासन का ढिंढोरा पीटने वाला ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कितना स्वच्छ प्रशासन दे रहा है। कि साके महाभ्रष्टों और मोटी चमड़ी के डकैतों को इसीलिये आईएएस बनाया गया ताकि वे बड़ी आसानी से रु पांच करोड़ खर्च करके रु पांच सौ करोड़ कमाएं और रुपये 250 करोड़ इनके कदमों में डाल दें अब जब कि आशतोष अवस्थी की याचिका खारिज हो चुकी है। तो उसका आईएएस अवार्ड वापिस लेकर उसकी जांच करना चाहिए वहीं पी एच ई के डामोर की भी प्रमुख अभियंता से कार्यपालन अभियंता बनाकर जांच की जानी चाहिए क्यों कि भ्रष्टाचार के समय वह कार्यपालन यंत्री था।

वास्तविकता में तो भ्रष्टो की सरकार भ्रष्टों को पालेगी क्यों कि जो जितना बड़ा डकैत होगा उतनी बड़ी लूट करेगा और लुटाएगा और सत्ता में फिर चने मूगफली खाने नहीं आए नेता और मंत्री को लुटने लुटाने आये हैं। इसलिये हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे।

राष्ट्रगीत में लोकनायक गायें, हटायें अधिनायक

पेज 1 का शेष

और वंदे मातरम् को ही राष्ट्र गीत बनाने की लगातार पहल भी की जाती रही पर इसे कांग्रेस का चारित्रिक दोगुलापन कहा जाये या गुलाम मानसिकता का असर कि ढंग से जनता के सामने विशेषतौर पर मुसलमानों के सामने प्रस्तुति और उनकी भाषा में व्याख्या ही नहीं कर पाये, अन्यथा भारत में वंदे मातरम् का कोई विरोध कभी नहीं होता। दूसरी ओर वंदे मातरम् को कांग्रेस इसलिये भी जानबूझकर लागू करने देना नहीं चाहती की वह संस्कृत में है, जो सीधे भाजपा की सांस्कृतिक परंपरावादी सोच को दर्शाकर जन-मन को भाजपा की तरफ चलेगा, परन्तु वंदे मातरम् ही मात्र ऐसा राष्ट्रगीत है। जो राष्ट्रप्रेम जाग्रत करता है। जन के मन में राष्ट्रीयता एकता, सांस्कृतिक विशालता के साथ मधुरता के भाव देता है।

जबकि जन-गण-मन तभी तक राष्ट्रगीत होता है, जब तक उसकी वास्तविकता समझ में नहीं आती, जैसे ही उसकी गुलाम मानसिकता और अंग्रेजों की अधिनायकवादी मानसिकता का मार्ग प्रगट होता है, उसके बाद तो न तो कोई राष्ट्रभक्त इसे स्वयं गा सकता है, न सामने गाते या बजते देखकर सम्मान में सिर झुका सकता है। पहली लाइन में अधिनायक दूसरी में भाग्य विधाता, 7वीं में तब शुभ नामे जागे, तब आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। 11वीं लाइन में पुनः अधिनायक 12वीं में भारत भाग्य विधाता में से अधिनायक को लोकनायक में बदल देने से कम से कम गुलामी तो परिभाषित नहीं हो? वैसे तो पूरे गीत में स्व. र.ना. ठाकुर ने ठाकुर होने के बाद भी अपने खानदानी अंग्रेजों के तलुओं चाटने और न केवल स्वयं वरन् पूरे भारत की जनता, सारे प्रांतों, नदी, पहाड़ों से अंग्रेजों की गाथा और आस सु मांगे, 65 वर्ष की आजादी के बाद भी गाया जा रहा है। दूसरी ओर जैसी भावनायें, इच्छायें प्रार्थना करेंगे। वही तो मिलेगा, राष्ट्रगीत में गुलामी की कामना कर रहे हैं। 125 करोड़ तो पुनः गुलामी ही मिलेगी न। गीत नहीं बदल पा रहे हैं, तो अधिनायक को पहली और दसवीं लाइन से हटाकर लोकनायक गायें तो गुलामी की कामना इच्छा और उसके अभिशाप से अवश्य मुक्त रह सकेंगे, बेशक देश के धूर्त सत्ताधीशों को बस कमीशन मिलता रहें, तो गुलामी तो क्या ट्रायल के बहाने जनता को सन् 2005 से हर वर्ष पूरे देश के सरकारी और निजी औषधालयों और चिकित्सालयों में सवा लाख से ज्यादा हैं। मात्र औसतन लगभग 20 से 30 लाख लोगों को अकाल मृत्यु के मुंह में झोंक रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है हमारे धूर्त गिद्ध सत्ताधीशों के बारे में।

खाद बीज कीटनाशकों के लायसेंसिंग में चलती है मोटी रिश्वत

भ्रष्ट अधिकारियों के कारण लुटता है किसान

हजारों प्रकरणों में प्रकरण मात्र ऊपर मंत्री से संत्री तक पैसे का खेल

म.प्र में मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी घोषणाएं कर जनता को बड़े सब्ज बाग दिखाते हैं। कृषि को लाभ का धंधा बनाएंगे किसानों को खुशहाल बनाएंगे। अलग के कृषि केबिनेट होगी इन सब योजनाओं के विपरीत पूरा कृषि विभाग संचालक से लेकर नीचे गांवों में कृषि विकाश अधिकारी अद्यानिकी विभाग के कर्मचारी अधिकारी मिल कर किसानों के साथ अपनी जेबें भरने के लिए हर कदम छलकपट लूट करते और करवाते हैं।

पूरे कृषि और कृषि से जुड़े उद्यानिकी विभाग बीज प्रमाणीकरण संस्था से लेकर मप्र किसान विपणन संघ मप्र कृषि फार्मस एंड सीड्स कारपोशन आदि सभी में चारो तरफ भारी भ्रष्टाचार होने के कारण सबका भुगतान अंत में किसानो की कड़ी मेहनत बर्बादी और जेब से होता है। इसके चलते देश में लाखों करोड़ों रुपये के अनुदान केन्द्र व राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं मे किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इसके विपरीत किसान हमेशा ऋण में लदा रहता है। और यहीं ऋण का भार अंत में जब ज्यादा हो जाता है तो आत्म हत्या कर लेता है। जिससे लाखों किसान देश में आकाल मौत मरते हैं। जिसके पीछे न केवल सरकार की नीतियां जो केवल भ्रष्टाचार से धन कमाने औव किसानों के शोषण का कार्य ही करती है। बाकी की बची हुई कसर वहां अजगर की भांति बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी कर देते हैं। क्यों कि 5 से 15 वर्षो से बैठे एक ही पद और एक ही स्थान पर बैठेंगे तो चारों तरफ जमावट से महीना वसूली कर नकली स्तर टीन कम गुणवत्ता के खाद बीज कीटनाशकों के विक्रेताओं को 25000 नए लाइसेंस के 15000 हजार लायसेंस के नवीनीकरण के वसूल कर पूरे मप्र के जिलों के उपसंचालक सहा. संचालक खाद बीज कीटनाशक निरीक्षक सारी भारी भरकम 40 पेजों की औपचारिकताएं पूरी करवा कर आंखमींच कर लाइसेंस जारी कर देते हैं। स्वाभाविक है कि जब खाद बीज कीटनाशक विक्रेता भी नकली स्तरहीन या कम गुणवत्ता का मल बेंच कर भी चौगुना लाभ कमाएगा। उसे मालूम है कि सब भ्रष्ट है नमूने लेने पर यदि अमानक मिलावटी नकली स्तरहीन या कम गुणवत्ता के भी पाए जाने पर तो भी सारा खेल बचाने का विभागीय निरिक्षक उपसंचालक सहायक संचालक कृषि अधिकारी स्वयं ही करेगा और 90 प्रतिशत स्तरहींन नमूनों को भी वो सफलता से थोड़ा बहुत धन लेकर घोषित करवा देगा। यहां लगी हुई सूचि से पाठक जाने सकेंगे कि एक तो पूरे प्रदेश की कृषि विभाग में खाद बीज कीटनाशकों के निरिक्षकों की फौज ही आलादर्जे न केवल निकम्मी और भ्रष्ट है वरन जमावट के चलते समाचार पत्रों में धूप समचारों, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में नमूने ले भी लेंगे तो स्वयं ही प्रयोगशाला में जाकर लेन देन कर ही समाप्त कर देंगे। इस सूची में देखेंगे कि पूरे प्रदेश में कीटनाशकों के मात्र 162 ही नमूने लिये गए। जब कि पूरे प्रदेश में 100 से ज्यादा उत्पादक और 500 से ज्यादा पेकर्स गांवों और शहरों में कुल मिलाकर औसतन 100 से ज्यादा कीटनाशक प्रति जिला मान लें तो 5000 से ज्यादा विक्रेता होने के बाद कुल नमूने 162 लिए गए अंदाजा लगाया जा सकता है कि जमावट महीना वसूली का खेल कितना लंबा है। यही हाल खाद बीज का भी हैं। मानक बीज के नाम पर प्रमाणीकरण संस्था और उपसंचालक कृषि जो 50 जिलों के 50 उपसंचालक कृषि बीज उत्पादक संस्थाओं जो प्रदेश में 400 से ज्यादा हैं। और अधिकांश नेता और कृषि माफियाओं की है। शासन ने मिलने वाले अनुदान का 50-50 प्रतीशत के आधार पर सौदा कर धड़ल्ले से बाजार से बीज के नाम पर कृषि उत्पादन खरीद कर पेक करती है और बीज प्रमाणीकरण संस्था से टेगिंग कर स्तरहीन बीजों को भी किसनों को बेंच देती है। टेगिंग किए बीजों का जब नमूना लिया गया तो उसमें चालिस प्रतीशत अंकुरण होना पाया गया। 45 प्रतिशत से ज्यादा नमी पाई गई जो कि स्तरहीन के पार्याप्त साक्ष्य थे इसके विपरीत बीज बेंचा गया फिर ईगल सीड्स जैसी अनेकों कर्पोरेट कं. भी लेन देन कर बाजारों से खरीदे बीज को ही पैक करके वर्षो से बाजार में बेंच रही हैं। बीज उत्पादक संस्थाएं ईगल जैसी कार्पोरेट कं. बीज प्रमाणीकरण संस्था की केवल कागजीखाना पूर्ति कर लेने देन करके टैगिंग करवाकर आरबों रुपयों का बीज हर वर्ष इंदौर से पूरे प्रदेश में और राजस्थान और महाराष्ट्र गुजरात जैसे अनेकों राज्यों में बेंच रही हैं।

अकेले इंदौर में वर्षो से जमें दो सहायक संचालकों के स्थानांतरण होने पर जिसमें एक तो करोड़ों की संपत्ति का देपालपुर और इंदौर में इकट्ठी कर चुका है। पेटी नोट खर्च करके रुकवा लाया दूसरा भी पेटी नोट खर्च करके रद्द करवाने की तैयारी में हैं। पाठक अंदाज लगा सकते हैं कि 10-15 वर्षो से जमे अधिकारी लाख दो लाख खर्च करके स्थानांतरण रुकवाते हैं, जो कमाते कितना हैं। यहीं भ्रष्टाचार किसानों की बर्बादी का मूल कारण है। तो विक्रेता और उत्पादक क्यों असली अन्छा गुणवत्ता युक्त खाद बीज कीटनाशक बेचेंगे।

जहां तक मुख्यमंत्री कृषि मंत्री अन्य नेताओं का है तो नेता तो जन्मजात घोषणा वीर होते है।

कार्रवाई की ताजा स्थिति

विवरण	कीटनाशक	खाद	बीज
विश्लेषित नमूने	162	1780	2628
मानक नमूने	153	1498	2049
अमानक नमूने	09	282	579
विक्रय प्रतिबंधित	19	282	579
चेतावनी	02	282	0
कारण बताओ नोटिस	20	0	0
लायसेंस निलंबित	07	16	26
लायसेंस निरस्त	07	03	07
एफआईआर	01	02	02
न्यायालय में प्रकरण	03	00	00

पूरे राष्ट्र में होता है अवैध उत्खनन में

रु. 10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला रायल्टी का

अकेले म.प्र. में ही रु 10000 करोड़ से ज्यादा चोरी अवैध उत्खनन से

भारत की धरती में रत्न गर्मा कहीं जाती रही है। और यह सहस्त्रों वर्ष पुराना सच वर्तमान में और बड़ा सच बन चुका है। इस राष्ट्र की धरती में हीरा पन्ना से लेकर मोनोजाईट क्रोमोजाईट सोना चांदी तांबा लोहा एल्युमीनियम से लेकर रेती मुरम तक का अवैध उत्खनन पूरे राष्ट्र में लाखों स्थानों पर होता है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस येदीयुरप्पा पर भी लोकायुक्त कर्नाटक ने अवैध उत्खनन में सीधे ही उनकी संलिप्तता पर आरोप पत्र तैयार कर लिया है। और उनकी कुर्सी इस अवैध उत्खनन कांड में ही गई। अवैध उत्खनन का काम पूरे देश में लाखों करोड़ों का है। इसमें न केवल हीरे व पन्ने जैसे बहुमूल्य रत्नों के साथ ही स्वर्ण रजत तांबा व लोहा जस्ता अमक एल्युमीनियम जैसी अमूल्य धातुओं से लेकर पत्थर गिट्टी कोयला कच्ची मुरम चूना तक की शासन को मिलने वाली रायल्टी की चोरी पूरे राष्ट्र में रू. 10 लाख से ज्यादा की चोरी की जा रही है। इस चोरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जमशेदपुर से टाटा स्टील में एक स्ताब्दी से ज्यादा समय से लोहे अयस्कों से जो लोहा निकालकर बेंचा जाता है। इसके विपरीत टाटा के पास अयस्कों की एक भी खदान नहीं हैं। वहां अधिकतर गांवों की जमीनों से गांव वाले खोदकर लाकर बेंचा जाता हैं।जिसकी न्यूनतम रायल्टी भा सरकार को बराबर नहीं मिलती जबकि बिहार छत्तिसगढ़ झारखंड जैसे प्रदेश अपनी खनिज संपदा के कारण ही पूरे विश्व में कई बहुमूल्य धातुओं के कारण विश्व विख्यात हैं। जब कि काश्मीर से लेकर कर्नाटक तमिलनाडु और महाराष्ट्र गुजरात से लेकर सुदुर पूर्वोत्तर राज्यों मे भी खनिज संपदाये वैध अवैध तरीकों से दोहन की जाती है। जिसमें अधिकांश सांसद चाहे वे किसी भी प्रदेश के हो पूरे देश में अधिकांश प्रदेश की सत्ताओं में विधानसभा के अधिकांश विधायक कहीं न कहीं अवैध उत्खनन में गहराई तक जुड़े रहते हैं। चाहे वो उसके क्षेत्र में बहने वाली नदियों की रेत के अवैध संग्रहण से जुड़ी हुई हो या उसके क्षेत्र से लेकर आस पड़ोस के क्षेत्र में पाई जाने वाली खनिज संपदा में जिसमें पत्थरों को बीन एकत्र कर गिट्टी बनाने वाले क्रेसरों से लेकर रेती के अवैध दोहन से आगे चूना जो नर्मदा घाटी के होशंगाबाद से ऊपर के क्षेत्रों में लोह तांबा जैसे खनिज पदार्थो से लेकर हीरे आदि जो सतना से लेकर पन्ना छतरपुर और रीवा के क्षेत्रों में पाया जाता है। वास्तविकता में सरकार के खजाने में 10 प्रतिशत रायल्टी भी नहीं आती है। फिर अमुक मैग्नीज तांबा आदि का 90 प्रतिशत अवैध उत्खनन होता है। कोयला जो केन्द्र की कंपनियों द्वारा किया जाता है। मात्र 50 प्रतिशत रायल्टी का ही भुगतान करती है। 50 प्रतिशत का माल निकाल कर उनके अधिकारी कर्मचारी खुले बाजार में बेंच कर माल डकार जाते हैं। जिसमें केन्द्रीय खनन मंत्री के साथ प्रदेश के खनन मंत्री का भी हिस्सा होता है। अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंदौर का खनिज निरिक्षक संजय लुनावत इंदौर में घुसने वाले रेती के ट्रकों की रायल्टी क्रेसर में लगने वाले पत्थरों की अवैध कुटाई की वसूली भर से ही अकेले एक

लाख रू औसतन वसूलता है। प्रतिदिन यही कारण है कि उसके इतनी बार स्थानांतरण किये गए पर वो हर बार पैसे खर्च करके मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी से जमावट कर स्थानांतरण रद्द करवा लेता है। और उसकी लूट और वसूली का खेल फिर शुरू हो जाता है। जब ये हालात इंदौर जैसे जिले के हैं। जहां कोई बहुमूल्य खनिज अब तक वर्तमान तक प्राप्त नहीं हुआ है। केवल गिट्टी पत्थर कच्ची मुरम के दम पर एक खनिज निरीक्षक रू. एक लाख प्रतिदिन तक की कमाई कर सकता है। जहां बहुमूल्य धातुओं की खनिजों की हीरा पन्ना लोहा सोना तांबा चांदी चूना कोयला अम्रक क्रोमोजाइट मोनोजाइट से लेकर यूरेनियम थोरियम प्लूपेनियम आदि पाये जाते हैं वहां अवैध उत्खनन से कैसे हर माह अरबों रु. की चोरी की जाती है। अंदाजा लगाया जा सकता है।

अकेले म.प्र में ही राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य के राजमार्गो को जो बीओटी के अतंगर्त ठेकेदारों को सौंप कर पुनः हजारों किमी. की सड़कों को एक से दो दो से चार और चार से पांच लेन में बदला गया। इन ठेकेदारों ने पिछले पांच वर्षो में ही सरकार को अवैध पत्थरों और कच्ची मुरम के उत्खनन से ही रुपये 3000 करोड़ का चूना लगा दिया। 3000 किमी के राजमार्गो के निर्माण एजेंसी म.प्र. रोड उकैत कार्यो ने करवाई थी, दूसरी और राष्ट्रीय राजमार्गो की एजेंसी राष्ट्रीय राजमार्ग लूट प्राधिकरण ने भी लगभग 2000 किमी से ज्यादा मार्गो को ठेकेदारों को सौंप दिया है। मानकर चलें कि मांग रुपये एक करोड़ प्रति किमि. की रायल्टी चुकाना थी तो रुपये 5000 करोड़ की नुकसान म.प्र. शासन के खनिज विभाग को हुआ इस तथ्य को समय माया ने वर्षो पूर्व भी उठाया था। और खनिज विभाग से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी भी मांगी थी पर हराम खोरों और डकैतों की फौंज ने उसे बीच में लटका दिया। दूसरी अपील भी की गई पर भ्रष्टों वहां पर टुकड़ा डाला और वहां बैठे सेवानिवृत्त इंडियन एयूसिंस सर्विस के मुखौटे इकबाल अहमद को खरीद लिया और मुख्यालय जानकारी एकत्रित एकत्रकर जबकि जानकारी हर माह मुख्यालय खनिज विभाग मप्र को भेजी जाती है। जिस पर ऑख मीच कर कचरे के ढेर में पटक जाती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग तो लिये पर सुधार के लिए धन नहीं

भोपाल। मुख्यमंत्री की दरख्वास्त को स्वीकार कर केंद्र ने मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय राजमार्गों की जिम्मेदारी तो दे दी, किन बजट नहीं दिया। इसका फायदा राज्य में कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार को घेरने में उठा रही है। इतना ही नहीं अब मुख्यमंत्री इस बात को लेकर नाराज है कि कांग्रेस दोहरा खेल खेल रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति फिलहाल समाप्त होती नहीं दिख रही है। खस्ताहाल सड़कें और मप्र सरकार के बढ़ते दबाव के बीच केंद्र सरकार ने सड़कें तो प्रदेश के हवाले कर दी है। लेकिन बजट के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने केन्द्र से नाराजगी जाहिर की है। शासन ने सड़कों के रखरखाव के लिए 94 करोड़ रुपए के बजट की मांग रखी है।

राजनीतिक रंग लिया विवाद ने

केन्द्र और राज्य सरकार के बीच राजमार्गों के रख रखाव को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रूप ले चुका है। प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों को लेकर प्रदेश भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने है। प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भाजपा जहां केन्द्र को जिम्मेदार ठहरा रही है।

चार राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदेश के हवाले

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बार-बार आग्रह करने और बढ़ते राजनीतिक दबाव में केन्द्र ने चार प्रमुख मार्गों को मप्र के हवाले कर दिया है। इसमें जबलपुर से भोपाल, कटनी, शहडोल, अनूपपुर से होकर छत्तीसगढ़ तक ब्यावरा से राजस्थान बार्डर तक की सड़कें शामिल है। इन राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 785 किमीं है। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित कर केन्द्र से 3000 किमी लंबी सड़कों की मांग की थी। इसमें 10 राजमार्ग शामिल थे। लेकिन फिलहाल केन्द्र चार राष्ट्रीय राजमार्गों को ही प्रदेश के हवाले किया है।

मरम्मत के लिए चाहिए 1000 करोड़

प्रदेश से करीब 4700 किमी की सड़के गुजरती ह। कुछ सड़कों को छोड़कर सभी की हालत बेहद खस्ताहाल है। विभागीय अधिकारियों का तर्क है कि इन सड़कों की मरम्मत के लिए कम से कम एक हजार करोड़ रुपए की जरुरत पड़ेगी। इसमें भी यदि तात्कालिक रूप से कुछ सड़कों का काम शुरू किया जाए तो भी 200 करोड़ रुपए की जरुरत होगी। ऐसे में बिना बजट के एनएच की मरम्मत का काम प्रदेश को देने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि प्रदेश सरकार ने चार सड़कों की मरम्मत के लिए फिलहाल 94 करोड़ रुपए का पूर्वानुमान तैयार कर केन्द्र को भेजा है। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में इसके मिलने की उम्मीद भी कम ही दिखाई दे रही है। ऐसे में केन्द्र और राज्य सरकार के बीच चल रहा राजनीतिक घमासान और बढ़ने की उम्मीद है।

साप्ताहिक समय माया

भारत के लोकतंत्र में आंदोलन ही निकाल बचा है, तो

आंदोलन करना ही होगा इन भ्रष्टाचारों के विरुद्ध

पेट्रोल पंपों, मोबाइल सेवा में हर दिन अरबों की लूट पर युवा पीढ़ी देती छूट

राष्ट्र में अन्ना के आंदोलन से यदि एक लोकपा बिल लागू भी कर दिया तो खास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कानून को लागू और पालन तो सरकार ही करवायेगी, फिर यदि मु. न्यायालय प्रकरण भी चालू कर भी दिया गया तो 10-20 वर्ष प्रकरणों में फैसला ही नहीं आया, तो भी भ्रष्ट और अपराधी की जिंदगी तो खत्म ही हो जायेगी। अन्ना का आंदोलन लोकपाल बिल तक ही सीमित है।

जबकि जनता स्वयं ही हर कदम भ्रष्टाचार को झेलती है जैसे कि 1. सभी मोबाइल कं. हर मिनिट, काल ड्रापिंग, काल चार्जेस, कॉलर ट्यून, रिंगटोन, आवाज न आने, न जाने, एसएमएस, एमएमएस के नाम पर करोड़ों रु. की लूट करती हैं। युवा पीढ़ी जिसके पास समय है, तो वो तो बहस भी करते हैं। पर जिनके पास समय नहीं है, जो जानते नहीं, जो जानकर भी कौन लड़ाई-झगड़े में पड़े चुप रह जाते हैं। पर इन हरामखोर जालसाज कं. जिसमें रिलायंस, इंफो, स्मार्ट, भारती, एयरटेल, टाटा, आइडिया, विडियोकॉन, बीएसएनएल, राष्ट्र की सभी कंपनियां शामिल हैं। टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी जो इनकी नियामक संस्था है, भी कुछ भी नहीं करती, यही कारण है कि सिंगल, 2 जी, 3जी सबमें अरबों रु. प्रति माह की हर कंपनी लूट करती है। इसके खिलाफ आंदोलन करना ही पड़ेगा।

2. पेट्रोल, डीजल और गैस पंपोंप र मिलावट और कम नाप से भी न केवल हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन आइल, रिलायंस, एस्सार कं. भी लूट रही है। जनता को हर कदम-कदम पर हर कंपनी हॉकरों का वेतन और ड्रेस देती है। ड्रेस तो पेट्रोल पंप मालिक, पहन नहीं सकता परन्तु वेतन हॉकरों का वो डकार जाता है और हॉकरों से प्रति लीटर वो और 1 से 3 रु. तक उल्टा ही वसूलता है। कमीशन के अतिरिक्त, स्वाभाविक है, हॉकरों को चोरी करके ही बंदरबांट करनी पड़ती है।

म.प्र. में गैस लीटर से बिकवाई जाती है। जिसमें मात्र 500 से 600 ग्राम गैस मिलती है। जबकि गैस को तौलकर बेचा जाना चाहिए। समय माया पेट्रोल के पाइप के नोजल के पहले पाइप के कोने पर पारदर्शी पाइप लगाने के लिये न केवल लिख रहा है वरन कं. को भी लिखा गया, खाद्य निरीक्षक से लेकर नियंत्रक, जिलाधीश और मंत्री को भी कहा गया परन्तु कोई सुनने को तैयार नहीं, वर्तमान में हर घर में दोपहिया वाहन तो हैं है साथ उच्च, मध्यमवर्गीय से लेकर ऊपर उच्च आय वाले हर घर में कारें भी हैं। हर कदम-कदम वाहन चालक इन पेट्रोल-डीजल और गैस पंपों पर मिलावट और कम नाप से लूटा ही जाता है। इस पर भी आंदोलन करना चाहिये। जनता को।

3. अमेरिका और विश्व व्यापार संगठन के इशारे पर राष्ट्र के राज्यों के सारे विद्युत मंडलों को भंग करके पूंजीवाद की तरफ बढ़ते हुए सभी की अलग-अलग कंपनियां हर प्रदेश में बना दी गई है। इन जालसाज कंपनियों में बैठे इंडियन एक्यूसिंग सर्विस के अधिकारी जिन्हें हरामखोरों का विद्युत का अ ब स द भी नहीं आता हर वर्ष रु. 300 से 1000 करोड़ तक डकार कर हर कंपनी को बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को सौंपने के लिये जालसाजों की ये फौज हर विद्युत उत्पादन वितरण की कंपनियों को घाटे में दिखाकर डुबोने पर लगी है। जबकि इलेक्ट्रानिक मीटर जो 60 से 200% तक तेज चलते हैं। एक तरफ जनता को लूट रही हैं, तो दूसरी तरफ मंडल के ताप और जल विद्युत ग्रहों का जानबूझकर रखरखाव की राशि हजम कर उन उत्पादन केन्द्रों को कभी कोयले की कमी के नाम पर पुराने होने के नाम पर बंद करने पर तुली है। अकेले म.प्र. में ही सारणी के संजयगांधी ताप विद्युत ग्रहों को इसी प्रकार बर्बाद कर 25 पै. यूनिट की बिजली को रु. 6 से 16 रु. तक में बेच कर भी घाटा दिखाया जा रहा है। म.प्र. में ही सन् 1995 से हर वर्ष में एक बार 1999 से वर्ष में दो बार बिजली की कीमतों में लगातार वृद्धि कर जनता को हर तरफ से लूटा जा रहा है। आंदोलन इसके विरुद्ध भी करना चाहिये

जनता को।

4. सन् 1987 से पेट्रोल, डीजल के साथ ही अन्य सेवाओं, यहां तक की आय कर भी 2% शिक्षा शुल्क का सेस वसूला जा रहा है। जबकि उच्च शिक्षा का 90% व्यावसायीकरण हो चुका है। शासकीय शिक्षा का लाभ मात्र 10% गरीब ही उठा पा रहे हैं। शिक्षा दिनोंदिन नर्सरी से लेकर महाविद्यालयों तक की पिछले 20 वर्षों में 200 से 2000% तक महंगी हो चुकी है। आम गरीब के नाम पर वसूले जाने वाले धन की केन्द्र से लेकर राज्यों तक भारी बंदरबांट हो रही है, जन शिक्षा अभियान, सर्वशिक्षा अभियान में अकेले म.प्र. में ही रु. 2000 करोड़ रु. विशुद्ध हजम किये जा रहे हैं। इस लूट और भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी जनता को आंदोलन करना ही चाहिये।

5. सन् 1999 से शिक्षा उपकर की तरह ही 2% सड़क शुल्क भी वसूला जा रहा है। जो विशुद्ध रूप से नई सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिये ही होता है। इसके साथ ही 32% केन्द्र ैर 36% राज्य सरकारें पेट्रोल, डीजल और गैस पर कर वसूल कर रही है। 7% नये वाहनों के पंजीयन पर रोड टैक्स के नाम पर वसूला जाता है। इसके विपरीत इस लोकतांत्रिक राष्ट्र को लूटतांत्रिक राष्ट्र बनाकर हरामखोर केन्द्र व राज्य के सत्ताधीशों ने सड़कों पर खर्च किये जाने वाले पैसे को हजम कर राज्यों ने राज्य के राजमार्गों पर और केन्द्र ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर देश 70000 कि.मी. मार्ग पर और राज्यों ने लगभग 5 लाख कि.मी. मार्ग पर टोलटैक्स मोटे कमीशन टोल टैक्स ठेकेदारों से डकार कर लगा दिये हैं। इसके विरुद्ध भी जनता को सड़कों पर उतरकर ही आंदोलन करना पड़ेगा।

6. केन्द्र व राज्य सरकारों को खाद्य वस्तुओं पर शासकीय करों के अतिरिक्त मोटा कमीशन नहीं मिल पा रहा था, इसलिये केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूंजीपतियों के इशारे पर नाचकर और मोटा कमीशन डकार कर खाद्य सुरक्षा और मानक अधि. 06 बना दिया चूंकि उसमें सभी को कमीशन मिलना था भाजपा ने भी इस अधिनियम के बिल पर मोटा चान डकार कर आंख मींचकर हस्ताक्षर कर दिये।

केन्द्र सरकार इसकी पूरी तैयारी पिछले 5 वर्ष से कर रही थी पर उपयुक्त मौके की तलाश में थी जब देशक के दृश्य और श्रव्य मीडिया और जनता का ध्यान उसी में लगा रहे और केन्द्र सरकार आसानी से इस अधिनियम को पूरे देश में लागू कर सके, मार्च से चलने वाले अन्ना और रामदेव के आंदोलन और अनशन के समय जब पूरे दृश्य-श्रव्य और मुद्रित प्रसार माध्यमों का ध्यान इसमें उलझा कर जनता इसमें उलझा दिया गया, मई में अन्ना की घोषणा की 15 अगस्त से जनआंदोलन छेड़ा जायेगा, केन्द्र के धूर्त प्रधानमंत्री मनमोहन और उसके डकैतों की फौज प्रणव, चिदंबरम, गुलाम नबी आजाद, कपिल ने इसे 5 अगस्त से लागू कर दिया।

पिछले 20 वर्षों से केन्द्र व राज्य की सरकारें महा धूर्त जालसाज उद्योगपति मुकेश और अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की कठपुतली बनी हुई है, यह अधि. 06 उसी के रिलायंस फ्रेश के लिये अंबानी ब्रंधुओं के इशारे पर ही उन्हीं के लिये बनाया गया, वास्तविकता में ये खाद्य सुरक्षा के नाम पर रिलायंस फ्रेश सुरक्षा है, इसके चलते देश के महानगरों से लेकर गांवों तक चाय, पान, सब्जी, अनाज, किराने, मिठाई, फल, नमकीन, चाट, कचोड़ी, पकोड़ी, दूध के थोक व फूटकर व्यवसाय से जुड़े लगभग 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जायेंगे। जनता को सारा माल पैकेटों में रिलायंस की मनमानी कीमतों पर उनकी इच्छानुसार रिलायंस फ्रेश के माल्स से ही खरीदना पड़ेगा, इन शूकरों मुकेश और अनिल अंबानी जैसे जालसाज इसमें मिलावट करके कई गुना ज्यादा कीमतों पर बेचने पर सरकार का कोई अंकुश नहीं होगा, सरकारी शूकरों को नीचे से लेकर ऊपर तक महीना मिलेगा, उपजिलाधीश को ऐसे सभी थोक व फुटकर विक्रेताओं के विरुद्ध न्यूनतम रु. 25000 दंड करने का अधिकार होगा, तो ठेले वालों से लेकर रु. 10-20 हजार दैनिक के लेन-देन वाले दुकानदार कितनी बार रु. 25000 दंड भर सकेंगे। इस कानून को रद्द करवाने के लिये भी जनता को हर हाल में आंदोलन करना ही पड़ेगा।

प्रिंट मीडिया आखिर क्यों है, गरबा प्रायोजक

धार्मिक गरबा नृत्यों की आड़ में खुला यौनाचार

केन्द्र व राज्यों का प्रशासन जानता है, क्यों आती गरबों के बाद गर्भपातों की बाढ़

पूरे राष्ट्र में जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर और नवंबर तक त्योहारों और धार्मिक कार्यक्रमों की चारों तरफ धूम रहती है। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और बाजारों में रौनक के साथ ये त्यौहार करोड़ों लोगों के रोजगार का वर्ष भर साधन भी बने रहते हैं।

भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार धर्म अर्थ के बाद मनुष्यों में कामेच्छा को पूर्ण करने की इच्छा बलवती होती है। जिसकी पूर्ति का नवरात्र, रास, डांडिया वर्तमान में भी बड़ा सुलभ श्रेष्ठ विविधतायुक्त साधन बन चुका है। धार्मिक नवरात्रि पूजन की आड़ में शातिर वर्तमान में वृहत स्तर पर गरबों का आयोजन करते हैं जिसमें रिलायंस, आइडिया, एलजी, नोकिया से लेकर बड़ी-बड़ी अन्य कंपनियों इनके प्रतिनिधियों, अधिकारियों से लेकर निर्देशक स्तर के लोग भी इन कार्यक्रमों में हिस्सा मात्र इसी लिए ही लेते हैं कि इस गरबा रास डांडिया कार्यक्रमों के बहाने नवयौवनाओं, सुंदरियों का सत्संग, मेल-मिलाप और संसर्ग का भी अचूक अवसर विविधता के साथ प्राप्त हो जाये, सारे आनंद भी प्राप्त हो और सुरक्षा भी बनी रहे इसलिये बड़े समाचार-पत्रों के मालिकों यथा दैनिक भास्कर विद्यालय, नईदुनिया अभय प्रशाल, राज एक्सप्रेस विद्यालय, पत्रिका, पीपल्स समाचार लोकस्वामी, अग्निबाण, प्रभातकिरण जैसे क्षेत्रीय समाचार पत्रों से लेकर पूरे भारत में क्षेत्रीय स्तर पर ऐसे समाचार पत्रों जो आगे प्रायोजक बनाकर समाचार पत्रों के पत्रकारों, मालिकों व स्टॉफ के साथ मिलकर खुलकर रास रचाया जाता हैं। प्रकाशकों की आड़ और प्रायोजक होने के कारण पुलिस और प्रशासक वर्ग हर जिले का न केवल इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर वरन हर जिले से लेकर पूरे मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, आंध्रप्रदेश, केरल, कर्नाटक, हिमाचल, उत्तरांचल, पंजाब, असम अर्थात कुछ गिने चुने राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में नवरात्रि के गरबा आयोजनों में खुलकर डांडिया, गरबा और रास के बहाने यौनाचार रसपान किया जाता हैं। समय माया ने इस मामले को लगातार छापने और अन्य प्रकाशनों द्वारा इन तथ्यों पर प्रकाश डालने और संबंधित समाचार प्रकाशित होने के चलते अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालयों व प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे गरबा स्थलों के बाहर कंडोम वेंडिंग मशीनों की व्यवस्था करवा दी है। अर्थात रासलीला का भरपूर आनंद लो परन्तु रस कंडोम में संग्रहित कर पृथ्वी को अर्पित कर दो, ताकि पश्चातवर्ती परिणाम व्यथित न करें, इसके विपरीत अक्टूबर माह में हुये इन गरबों के परिणाम गर्भपातों के रुप में नवंबर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी तक सामने आने लगते हैं। रासलीला में बहे यौनाचार के रस से इन चारों महीनों में नवयौवनाओं में गर्भपातों की 10 से 25 गुना संख्या बढ़ जाती हैं। वैसे गर्भ निरोधक साधनों के भारी प्रचार-प्रसार से शातिर महिलायें जो 18-19 वर्ष से 35-40 वर्ष की होती हैं। पूर्व से ही गर्भनिरोधक गोलियों का भी लगातार इस्तेमाल कर अपने आप को गर्भ की अवस्था से बचा लेती हैं। परन्तु 12-13 वर्ष से 17-18 वर्ष की नवयौवनाओं रसपान तो कर लेती है परन्तु गर्भ ठहरने का शिकार हो जाती है। बेशक इन चारों महीनों में छोटे से छोटे गली मोहल्ले के नर्सिंग होम्स तक 5-10 गर्भपात नियमित रूप से करते हैं और नवयौवनाओं के संरक्षकों से सामाजिक डर की आड़ में मोटा धन ऐंठ लेते हैं। दूसरी ओर 24 घंटे टीवी चैनल पर बंटता प्रदर्शित किया जाता यौनाचार 10-11 वर्ष की लड़कियों को न केवल उत्तेजित करता हैं। वरन ऐसे कार्यक्रमों प्रायोजकों, आयोजकों से प्रतिभागियों की नजरें भी ऐसी नवयौवनाओं को उत्तेजित कर यौन रसपान पर ही टिकी रहती है। इसके विपरीत वयस्क और विवाहितायें चाहे फिर वह 50-60 वर्ष की ही क्यों न हो ऐसे गरबों, रास और डांडिया नृत्यों में प्रतिभागीयां दर्शक के बहाने शामिल होकर अवसरों का न केवल भरपूर लाभ लेने वरन यौनलोलुप महिलायें गिनती लगाकर पुरुषो से संसर्ग करने से नहीं चूकती, वात्सायन ने कामसूत्र में लिखा है कि महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मालवा की स्त्रियां अधिक कामातुर, बहुविधि इच्छायें धारित करती हैं। वर्तमान में भी सबसे ज्यादा गर्भपात इन्हीं क्षेत्रों में होते हैं। बेशक इसे रोका तो नहीं जा सकता, इसके विपरीत प्रायोजकों की मंशा अवश्य ही इससे प्रगट होती है, कि दुनिया को रास्ता दिखाने वाले स्वयं क्या है?

मप्र सरकार को चाहिये रा.रा. के अनुबंधों की समीक्षा

देवास-राऊ बाईपास अनुबंध को सौंपे सीबीआई को

42 कि.मी. 2 लेन मार्ग रु. 476 करोड़ का, बिना काम के वसूली क्यों और कैसे?

दक्षिण भारत के सांसद वाई एस आर रेड्डी पर आयकर और सीबीआई ने उसके कार्यालयों और घर पर छापेमार कर हजारों करोड़ रु. की जालसाजियों को पकड़ा। म.प्र. में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और इसी धूर्त वाई एस आर रेड्डी के बीच मात्र 42 कि.मी. सड़क को जिसमें पूर्व से ही यह मार्ग 4 लेन 20 कि.मी. डामर और 22 कि.मी. सीमेंट कांक्रीट का बना हुआ था, अर्थात 6 लेन मार्ग बनाने में मात्र 2 लेन और बनाई जानी थी जो प्रति कि.मी. रु. 2 से 3 करोड़ रु. में बन जानी चाहिये थी, वर्तमान केन्द्र व राज्य सरकार के एस ओ आरके हिसाब से, परन्तु 12 करोड़ रु. प्रति कि.मी. के हिसाब से 42 कि.मी. सड़क के लिये रु. 476 करोड़ रु. का अनुबंध क्यों किया गया। फिर दूसरी ओर अनुबंध में यह शर्त भी पूर्णतः जालसाजीपूर्ण है, कि कार्य शुरू करने के साथ ही बिना कुछ किये भी टोल वसूली शुरू हो जायेगी, तीसरा मांगलिया, इंदौर नगर निगम के कार्य क्षेत्र में आता हैं। तो दो टोल क्यों लगाये गये। एक मांगलिया में तिराहे से 1 कि.मी. पहले दूसरा बाईपास जबकि उसे मांगलिया तिराहे से 1 कि.मी. बाद मुख्य मार्ग पर लगाना चाहिये था, ताकि मुख्य मार्ग पर आने जाने वाले वाहनों से ही टोल वसूली हो सके, इसके विपरीत निगम की सीमा में दो अलग-अलग टोल लगाना न केवल गायत्री कंस्ट्रक्शन हैदराबाद जो वाई एस आर रेड्डी की जालसाज कं. है जिस पर हाल ही में सीबीआई ने चापा मारकर हजारो करोड़ रु. की इसी प्रकार इकट्ठी की गई अवैध संपत्ति और जालसाजियां पकड़ी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और गायत्री कंस्ट्रक्शन की अरबों रु. के ऊपरी लेन-देन और जालसाजियों से लूट का खुला हिस्सा है।

यही हाल इंदौर-अहमदाबाद रा.रा. मार्ग क्र. 59 का भी हैं, यहां पर ठेकेदार आइव्हीसाटीएल ने इस मार्ग का न तो दो वर्ष से ढंग से रखरखाव तो दूर न तो गड्ढे भरे और न ही इस हरामखोर ने मार्ग पूरा किया। यहां के परियोजना संचालक रा.रा.प्रा. से बात करने पर भी यह हरामखोर न तो ढंग से किसी को जवाब देता है,

(शेष पेज 2 पर)

स्वामित्वाधिकारी, प्रधान संपादक एवं प्रकाशक अजमेरा एस.पी. कुमार के लिए मीडिया वर्ल्ड कम्यु/ 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर के लिए नवनीत प्रिंटर्स जेल रोड, इंदौर से मुद्रित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9074551045, इंदौर कार्यालयः 0731- 2530859, मो. 9300755803